

दिल्ली परिवहन निगम भी आरटीवी की तरह खत्म के कगार पर....



संजय बाटला
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से सार्वजनिक सवारी सेवा प्रदान करने के लिए दिल्ली में नियुक्त दिल्ली परिवहन निगम को कर दिखाया खत्म जहा उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की जनता के हित को ध्यान रखते हुए आदेश पारित कर 100 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत सेवा प्रदान करने पर किया था। दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के नेतृत्व और मार्गदर्शन द्वारा अपने हित को ध्यान रखते हुए लिए ऐसे निर्णय की अगले वर्ष यानी 2024 के समाप्त होने तक दिल्ली परिवहन निगम भी हो जाएगी समाप्त दिल्ली की जनता को सेवा प्रदान करने वाले आरटीवी ऑपरेटर की तरह।

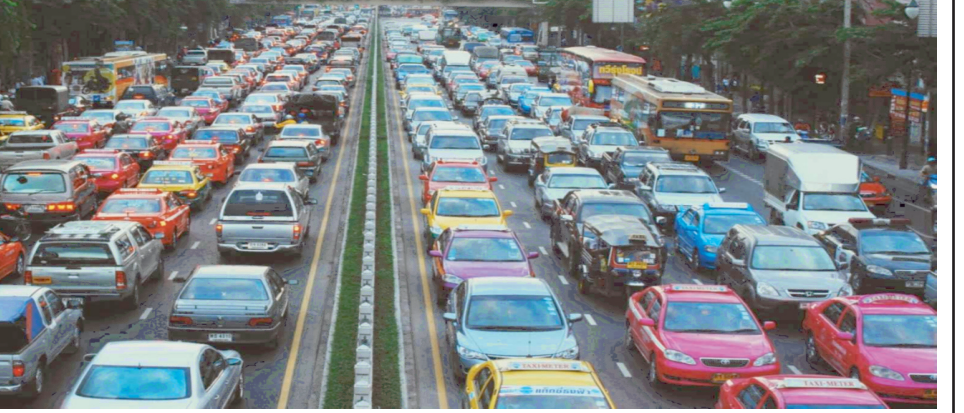
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स जंतर मंतर पर आज करेंगे विशाल धरना प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज
नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन दिनांक सोमवार, 30 अक्टूबर 2023 11 बजे विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने जा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार और उसके दिल्ली परिवहन विभाग एवं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा प्रदूषण के नाम पर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की डीजल BS 4 बसों को 1 नवम्बर 2023 से दिल्ली में एंटी बेन करने का तुलना की फरमान जारी कर दिया है ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की अभी इन्होंने दिल्ली एनसीआर की BS 4 डीजल बसें पूरी तरह बंद की हैं और बाद में पूरे भारत के डीजल BS 4 टैक्सी बसों को ये बंद करने वाले है। पूरे भारत के टैक्सी बस मालिक अभी हाल में ही 2 सालो से कोरोना महामारी से पीड़ित रहे हैं। दिल्ली सरकार एवं दिल्ली परिवहन विभाग और CAQM काफी समय से दुसरे राज्यों की सरकारी डिपो की परिवहन बसों को BS 6 डीजल या इलेक्ट्रिक या CNG गाड़ियों की एंटी के लिए दिल्ली में आने के लिए कह रहे हैं। ये खबर भी हमें अखबारों के माध्यम से पता चलती रहती थी. दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का आर्डर आया है जिसमें BS 4 डीजल बसों की एंटी 1 नवम्बर 2023 से बंद करने के आर्डर कर दिए गए हैं। जबकि इस से पहले एनसीआर दिल्ली की किसी भी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन को इस बारे में ना ही बताया गया और ना ही CAQM या दिल्ली सरकार द्वारा की गई किसी मीटिंग में बुलाया गया. संजय सम्राट का कहना है की पहले भी दिल्ली सरकार और कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा प्रदूषण के नाम पर डीजल से चलने वाली टूरिस्ट टैक्सी को पिछले साल भी ग्रेप लगाकर बंद किया गया, और उनपर 20 हजार तक जुर्माना भी किया गया. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की दिल्ली सरकार एवं उसका दिल्ली परिवहन विभाग और CAQM वास्तव में प्रदूषण के नाम टूरिस्ट टैक्सी बसों के मालिकों को ही टारगेट कर रही है, और जान भुजकर हमारी डीजल BS 4 बसों की एंटी दिल्ली एनसीआर में बंद करना चाहते है जबकि हमारी डीजल BS 4 बसें आल इंडिया टूरिस्ट परमिट है जो ज्यादातर दिल्ली से ज्यादा दुसरे राज्यों में पर्यटकों को घुमाने ले जाती है. पिछले साल भी इन्होंने 4 पहिये की डीजल BS 4 टैक्सी को बंद करा. लेकिन डीजल के ट्रक को खुले आम चलने की इज्जत दी. क्या डीजल की टैक्सी बसें पहिये के हिसाब से धुआँ देती है ?? ये सोचने वाला सवाल है. हमारे काफी ट्रांसपोर्टर्स ने 2019 के आखरी महीने में काफी डीजल की BS 4 बसें खरीदी अब 3 सालों में से 2 सालों बसें पार्किंग में ही खड़ी रही थी, अब इन गाड़ियों का क्या होगा ? इनकी किस्ते हम कहीं से भरेगे ?



डीजल टैक्सी बसें वो ही धुआँ अप्रैल महीने में देती है और वो धुआँ नवम्बर में, हमारी टैक्सी बसें सर्दी में कोई एक्स्ट्रा धुआँ नहीं देती. ये प्रदूषण की समस्या पराली जलाने से और पटखों की वजह से ज्यादा होता है, और सबसे बड़ी बात सर्दियों में मौसम बदलता ही है. अभी भी जो ग्रेप सिस्टम इन्होंने बनाया है उसमें डीजल BS 4 की 4 पहियों की गाड़ियों को ग्रेप 3 में रखा है जब AQI 401 से 450 के बीच में होगा. लेकिन जो डीजल BS 4 के ट्रक हजारों की संख्या में रात को आते हैं दिल्ली एनसीआर में उनको ग्रेप 4 में रखा है जब AQI 451 से ऊपर होगा. मतलब CAQM गाड़ी के पहियों के हिसाब से प्रदूषण का पैमाना बना रहा है. ट्रांसपोर्टर्स से जुड़े धंधे में हजारों बसों के मालिक जुड़े है इनके लाखो ड्राइवर्स हैं और करोड़ो परिवार इस से जुड़े है. क्योंकि इसका असर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स पर क्योंकि उनकी डीजल बसें दिल्ली एनसीआर में नहीं आ पाएंगी. संजय सम्राट का कहना है की अगर सवाल प्रदूषण का है तो पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की BS 4 डीजल बसों को आने की इज्जत क्यों दी गई है ? सिर्फ इन 3 राज्यों की डीजल बसें धुआँ देंगी और दुसरे राज्यों की बसें क्या ऑक्सीजन देंगी ?

सड़क यातायात की समस्याएं जिनका सुधार अभी बाकी है



संजय बाटला
नई दिल्ली। सड़कों की आरोही गुणवत्ता अत्यंत निम्नस्तरिय है। पुलों/पुलियों की हालत अभी भी कमजोर है। अधिकांश राजमार्गों की कुट्टिक मोटाई अपर्याप्त है। चैक पोस्टों, चुंगियों तथा रेलवे फाटकों की बड़ी संख्या अभी भी कायम है जो यातायात के प्रवाह को बाधित करती है और उनका समापत होना बाकी है। राजमार्ग अभी भी शहरों के सघन भीड़-भाड़ वाले भागों से होकर गुजर रहे हैं। सफर के समय मार्ग के दौरान मनोरंजन व अन्य जरूरी सुविधाओं का अभाव है तथा सड़क सुरक्षा उपाय भी अभी तक पर्याप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 20 प्रतिशत भाग को दो लेन वाले मार्ग में बदलने तथा दो लेने वाले राजमार्गों के 70 प्रतिशत भाग को द्रुत राजमार्ग में बदलने की जरूरत है। उत्तरी मैदानों में आड़ी-तिरछी बहने वाली अनेक नदियाँ तथा उनमें आने वाली बाढ़ों (प्रायः वार्षिक) के कारण सड़कों का निर्माण तथा रख-रखाव कठिन है उसके लिए टोस कदम उठाया जाना अभी बाकी है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या एवं उसके परिणामस्वरूप आवागमन के लिए निजी वाहनों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अनेक शहरों में वाहन जघनित प्रदूषण चेतावनी के स्तर को पार कर चुका है और सड़क क्षमता को बढ़ाना भी लगभग असंभव हो गया है, जबकि वाहनों की संख्या एवं यातायात सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही है।

बॉर्डर पर बीएस-3 और बीएस-4 बसों की होगी जांच



परिवहन विशेष न्यूज
नई दिल्ली। राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुँच गई है। ऐसे में इससे निपटने के लिए अलग-अलग पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में एक नवंबर से एनसीआर से दिल्ली आने वाले वाहनों में बीएस-तीन और बीएस-चार डीजल बसों की एंटी पर रोक रहेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को वाहन प्रदूषण को कम करने को लेकर कश्मीरी गेट बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एनसीआर राज्यों से आने वाली डीजल बसों के चालकों को जागरूक किया कि एक नवंबर से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी व बीएस-छह बसों को ही प्रवेश मिलेगा। गोपाल राय ने बताया कि केंद्र सरकार हरियाणा, यूपी और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में संचालित होने वाली बीएस-3 और बीएस-4 बसों को दिल्ली में प्रवेश को प्रतिबंधित करे। बुधवार से सभी बॉर्डर पर परिवहन विभाग जांच अभियान चलाएगा। दिल्ली में सभी बसें सीएनजी हैं। साथ ही, 800 से ज्यादा ई-बसें भी चल रही हैं, लेकिन यूपी, हरियाणा, राजस्थान के एनसीआर में चलने वाली बीएस-3 और बीएस-4 डीजल बसों के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। यूपी, हरियाणा व राजस्थान भी करे प्रतिबंध राय ने बताया कि आईएसबीटी में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यूपी और हरियाणा से जो भी बसें आई हैं वह सब बीएस-3 व बीएस-4 हैं। कोई भी बस इलेक्ट्रिक व सीएनजी की नहीं आई हैं। जो भी बसें नियम का पालन नहीं करेंगी, उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

टैपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय:- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

बाय-बाय 'काली पीली' टैक्सी, इस आइकॉनिक गाड़ी का मुंबई की सड़कों पर रविवार को रहा आखिरी दिन



परिवहन विशेष न्यूज
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछली प्रीमियर पंथिनी को तारदेओ आरटीओ में एक काली-पीली टैक्सी के रूप में पंजीकृत किया गया था जिसका अधिकार क्षेत्र मुंबई शहर पर है। चूंकि शहर में कैब की आयु सीमा 20 वर्ष है इसलिए मुंबई में आधिकारिक तौर पर सोमवार से प्रीमियर पंथिनी टैक्सी नहीं चलेगी। आइये डिटेल में जानते हैं। **नई दिल्ली।** मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के मन में मुंबई की एक तस्वीर बन जाती है, जिसमें बड़ा पाव, मरीन ड्राइव और काली पीली टैक्सी का प्रतिबिंब बनना आम बात है। हालांकि अफसोस कल से काली-पीली टैक्सी मुंबई की सड़कों पर नहीं दिखाई देगी। परिवहन विभाग ने 30 अक्टूबर से काली-पीली टैक्सी (प्रीमियर पंथिनी) को सड़कों पर चलने पर रोक लगा दिया है। जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल मुंबई में एक आखिरी काली-पीली टैक्सी बची है। **परिवहन विभाग का बयान** परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पिछली प्रीमियर पंथिनी को तारदेओ आरटीओ में एक काली-पीली टैक्सी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका अधिकार क्षेत्र मुंबई शहर पर है। चूंकि शहर में कैब की आयु सीमा 20 वर्ष है, इसलिए मुंबई में आधिकारिक तौर पर सोमवार से प्रीमियर पंथिनी टैक्सी नहीं चलेगी। **मुंबई की शान है ये कार** प्रीमियर पंथिनी टैक्सी मुंबई की शान है। इस गाड़ी को सबसे आखिरी में अब्दुल करीम कारसेकर नाम के व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब्दुल का कहना है कि ये केवल टैक्सी नहीं है, ये मुंबई की शान है और हमारी जान है। यह बदलाव सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बुहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाइ एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) द्वारा डबल डेकर डीजल बस को बंद करने के बाद आया, जिनका जीवन मुंबई की सड़कों पर केवल 15 साल तक का था। **संग्रहालय में संरक्षित करने की हो रही मांग** मुंबई घूमने जाने वाले लोग या फिर मुंबई की जनता डबल डेकर बस और काली-पीली टैक्सी को धरोहर की तरह देखती है, जिनको कल से मुंबई की सड़कों पर लोग खूब मिस करेंगे। ये वो गाड़ियां हैं, जिनसे बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हैं। कुछ लोगों ने मांग की है कि कम से कम एक 'प्रीमियर पंथिनी' को सड़क पर या संग्रहालय में संरक्षित किया जाए।

10 जोखिम कारक जो बढ़ा देते हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, बदल लें ये आदतें भी

कई जोखिम कारक होते हैं, जिसके कारण महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने की फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अधिक उम्र होना आदि. इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्हें आपको जानकर लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो सकती है.

अक्टूबर महीने को विश्व भर में 'ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ' के रूप में मनाया जाता है. इस पूरे महीने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है. इसके लक्षणों, कारणों के बारे में जनकारी दी जाती है, ताकि महिलाएं समय रहते स्तन कैंसर (Breast Cancer) का इलाज शुरू करा कर अपने जीवन को बचा सकें. दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर में स्तन कैंसर सबसे कॉमन है. हर साल लाखों महिलाएं इससे ग्रस्त होती हैं. आखिर किन कारणों से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आइए जानते हैं

कैसे होता है ब्रेस्ट कैंसर?

कैंसरसेंटर डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, महिलाओं में स्तन कैंसर तब होता है, जब ब्रेस्ट की कोशिकाओं में डीएनए उत्परिवर्तित (Mutate) या परिवर्तित होने लगता है. इससे कोशिकाओं में वृद्धि और विभाजन को कंट्रोल करने वाले खास कार्य अक्षम हो जाते हैं. कुछ मामलों में, ये उत्परिवर्तित कोशिकाएं मर जाती हैं या प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उन पर हमला किया जाता है. लेकिन कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली से बच जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिससे ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाता है.

ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स

कई जोखिम कारक हैं, जो महिलाओं में स्तन कैंसर होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं. इसमें कुछ ऐसे जोखिम कारक शामिल हैं, जिन्हें आप खुद से बदल नहीं सकते हैं, जैसे परिवार में ब्रेस्ट कैंसर होने की हिस्ट्री, जेनेटिक्स, अधिक उम्र होना. हालांकि, कुछ ऐसे भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन्हें रोककर ब्रेस्ट कैंसर के विकास की संभावनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है. हालांकि, कई बार जिन महिलाओं में कैंसर होने का जोखिम रहता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, वहीं जिनमें रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल नहीं होते, वे इस घातक कैंसर की चपेट में आ जाती हैं. हालांकि, हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनकर इस गंभीर बीमारी से काफी हद तक खुद को सुरक्षित रख सकती हैं. कुछ अन्य रिस्क



फैक्टर्स जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार हैं-
-55 या इससे अधिक उम्र होने पर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है.
- ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ाने के लिए जेंडर भी है एक मुख्य कारण है. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी काफी अधिक होती है.
- जो महिलाएं प्रतिदिन एल्कोहल का सेवन करती हैं, उनमें भी स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है.
- यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो इससे ना सिर्फ डायबिटीज, हार्ट डिजीज होता है, बल्कि

ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है.
- जो महिलाएं शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहती हैं या कम चलती-फिरती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम काफी अधिक होता है. ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें. ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग आदि करें. जितना ही आप फिजिकली एक्टिव रहेंगी, उतनी ही फिट और हेल्दी रह सकती हैं.
- कई बार पीरियड्स 12 साल की उम्र से पहले होने और 55 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज होने के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम कुछ महिलाओं में बढ़ जाता है.
- मां बनने के बाद यदि आपने अपने शिशु

को स्तनपान नहीं कराया, तो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ सकती है. ऐसे में शिशु के जन्म के बाद 6 महीने जरूर ब्रेस्टफीड कराएं.
- यदि परिवार में ब्लड रिलेशन में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो इस घातक बीमारी के होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है.
- कई बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को बढ़ा सकते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव का सेवन, बर्थ कंट्रोल शॉट, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट, बर्थ कंट्रोल स्किन पैचेज आदि के अधिक इस्तेमाल से भी इस कैंसर के होने का रिस्क बढ़ सकता है.

करवाचौथ पर हैंडमेड थाली से जीतें पति का दिल, 5 तरह से दें करवा सेट को आकर्षक लुक, देखते ही हर कोई करेगा तारीफ

करवा चौथ का त्योहार हिन्दू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लम्बी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. मान्यता है कि करवा चौथ के दिन पूजा करने और व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है. साथ ही तनाव दूर होता है. इस बार करवा चौथ का व्रत और पूजन 1 सितंबर को है. इस दिन को खास बनाने और पति की खुशी के लिए महिलाएं तमाम तरह की तैयारियां करती हैं. चाहें वो खुद के सजने-सवरने की बात हो या फिर करवा थाली सजाने की. दरअसल, पूजा थाली और करवा को आकर्षक लुक देकर आप पति का दिल आसानी से जीत सकती हैं. इसके लिए आपको साधारण करवा सेट लाकर उसको नया लुक देना है. आइए जानते हैं करवाचौथ का थाली सेट सजाने का आसान तरीका-

ऑयल से बनाएं डिजाइन: करवाचौथ की थाली को सुंदर डिजाइन देने के लिए आप तेल की मदद ले सकती हैं. इसके लिए आपको एक नई स्टील की थाली लेनी है. इसके बाद ईयर बड को किसी भी ऑयल में भिगोकर थाली में सुंदर डिजाइन बना लें. अब तेल वाले डिजाइन में सिंदूर, रोली, हल्दी या रंगोली के रंग डाल देंगे. हालांकि, ध्यान रहे कि, सभी को मिलाने के तुरंत बाद थाली को पलट देना है. ऐसा करने से पक्का रंग निकल जाएगा. इसके बाद डिजाइन की गिल्टर पेन से आउटलाइन बना देंगे.

थाली को पेंट से सजाएं: करवाचौथ पर अपनी पूजन की थाली को सबसे अलग बनाने के लिए आप पेंट की मदद ले सकती हैं. इसके लिए सबसे पहले थाली को शुभ रंग यानी लाल, गुलाबी या महरून से पेंट करें. जब पेंट सूख जाए, तब पतले ब्रश से इस पर सुंदर डिजाइन उकेरें. इसके



लिए आप थाली के बॉर्डर पर डिजाइन और मध्य में ओम या स्वस्तिक बना सकती हैं. आप चाहें तो बीच-बीच में हरे, पीले, सफेद और सिल्वर रंग का भी प्रयोग कर सकती हैं. इसके अलावा, बीच-बीच में मोटिफ्स को स्टेंस, मोती या सितारों से सजाएं. शीशे से थाली को दें लुक: शीशा जडित थाली बनाने के लिए थाली को फ्रिंट चुनरी से गोंद की मदद से चिपका देंगे. अब इसमें गोदा पट्टी के मोटिफ्स चिपकाएं. मोटिफ्स के आसपास गोंद की मदद से अलग-अलग आकार वाले शीशे चिपका देंगे. हालांकि, शीशे और जलन होने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक वाले शीशे से लुक उभरकर नहीं आता है. इसके बाद थाली के किनारों को मोतियों की लेस से सजा देंगे. इसकी जगह आप चाहें तो शीशे और धागे के लटकन से भी सजा सकते हैं. यही डेकोरेशन आप लोटे, दीपक और छलनी पर कर सकती हैं.

वेलवेट वाली रॉयल लुक: करवाचौथ के लिए वेलवेट वाली थाली शानदार विकल्प हो सकता है.

इसके लिए थाली पर लाल, गुलाबी या फिर महरून रंग का वेलवेट का कपड़ा चिपकाएं. ध्यान रखें कि कपड़ा सही तरीके से काटे, क्योंकि टेढ़ी-मेढ़ी कटिंग से रॉयल लुक फीका पड़ सकता है. इसके बाद थाली पर शीशे, फूल, मोती या गोदा पट्टी के पर्सनलाइज्ड करवा थाली के लिए आपको बाजार की मदद लेनी होगी. इसके लिए थाली, कलश, दीपक और छलनी खरीद होगा. फिर आप पति के साथ रोमांटिक फोटो पूरे करवा सेट पर छपवा लें. इससे आपका करवा सेट एकदम अलग दिखेगा।

केरल का 50 साल का हुआ, भारत का पहला महिला पुलिस थाना,इंदिरा गांधी ने किया था उदघाटन

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। भारत समेत एशिया के पहले महिला पुलिस स्टेशन को 50 साल हो गए हैं।पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केरल के कोझिकोड (वनीथा)में देश के पहले महिला पुलिस थाने का उदघाटन 23 अक्टूबर, 1973 को किया था। कोझिकोड वनीथा के इस महिला पुलिस स्टेशन की 'स्वर्ण जयंती' मनाई जा रही है। इस मौके पर 16 से 27 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।16 अक्टूबर स्वर्ण जयंती उदघाटन अवसर पर कोझिकोड सिटी की 50 महिला पुलिस कर्मियों ने अपने बाल कटवाकर और कौटुम्हिक स्थित महिलाओ और शिशुओ के अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए रक्त दान कर समारोह का आगाज किया गया। 18 को' पोलियुम कुटयोलुम' नाम से छोटे-छोटे बच्चों को वनिथा महिला पुलिस स्टेशन को अंदर से देखने और पुलिस अफसरों से बात करने के अलावा गीत, कविता करने का मौका दिया गया।20 अक्टूबर को सैंकडों की संख्या में महिला पुलिस कर्मियों ने नशे के खिलाफ बाईक रैली निकाली। यह बाईक रैली वेल्लयिल बीच से शुरू कर कोझिकोड टीम थाना, जन मैत्री अपना - कोझिकोड सिटी से घूमकर वापिस वनीथा महिला पुलिस थाने पर आकर डीआईजी एवं कोझिकोड पुलिस कमिश्नर राजपाल मीणा की निगरानी में समापन हुई। इसी दिन शाम को कारपम्पम् में महिला पुलिस कर्मियों के (क्रिकेट मैच) का भी उदघाटन एसपीओ सुदर्शन द्वारा किया गया। इसी क्रम में 21 अक्टूबर को कोझिकोड गोकुलम मॉल में वनीथा महिला पुलिस टीम द्वारा सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा करीब 50 महिला पुलिस कर्मियों ने मेगा-तिरुवातिरा का प्रदर्शन किया। वहीं बाद में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा कलरी-प्पयट्टु का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के तहत रात 10 बजे से 12 बजे तक महिला पुलिस कर्मियों द्वारा ('नाईट वॉक')का भी अभियान चलाया। इस निर्भरभयम्' - रात्री नटतम में कलक्टर टेय्यूटो ने भी भाग लिया।इस मौके पर सिनेमा अभिनेत्री सुरभि लक्ष्मी भी मौजूद थी।12 दिन तक चले 'महिला थाने के स्वर्ण जयंती



समारोह के अवसर पर 22 अक्टूबर को महिला पुलिस कर्मियों ने मिलकर पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर की सफाई भी की। अगले दिन कोझिकोड सिटी के सभी महिला पुलिस कर्मियों को कम्प्यूनिकेशन स्किल पर डाॅ अब्दुल गफूर ने अवेयरनेस पर लेक्चर दिया। 23 से लेकर समापन दिवस, 27 अक्टूबर तक सेमिनार, समेत वनीथा थाने की हेड तुलसी समेत तमाम महिला स्टाफ को कोझिकोड की डीसी केई बैजू कमिश्नर राजपाल मीणा के अध्यक्षीय भाषण के बाद सम्मानित किया गया। वहीं 25-,26-,27 अक्टूबर को स्वर्ण जयंती का मेगा कार्यक्रम हुआ। इसमें जस्टिस आर एल बैजू भी शामिल रहे। इसके अलावा केरल के मंत्री मुहम्मद रियास ने वूमैन सेप्टी एक्सपो 2023 का भी उदघाटन किया। अंत में 27 अक्टूबर को मंत्री मुहम्मद रियास द्वारा ही महिला थाने के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई।



भारत में कैंसर से महिलाओं को मौत का खतरा ज्यादा, लैसैट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा



लैसैट की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भले ही पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन कैंसर होने पर महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है. इसकी वजह सही समय पर कैंसर का पता न लगना और इलाज की कमी है. आज आपको बताएंगे कि महिलाएं किन तरीकों से कैंसर का पकट रहते पता लगा सकती हैं.

भारत में कैंसर से पीड़ित अधिकतर महिलाओं को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है. इसका खुलासा लैसैट कमीशन की नई रिपोर्ट में हुआ है. इसके अनुसार भारतीय महिलाओं में कैंसर के कारण होने वाली लगभग 63% मौतों को स्त्रीनिंग और निदान के जरिए रोका जा सकता था. जबकि 37% मौतों को समय पर सही इलाज से रोका जा सकता था. देश में कैंसर देखभाल में लैंगिक असमानता (gender inequity) पर लैसैट आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. इसमें कहा गया है कि भले ही पुरुषों में कैंसर का खतरा अधिक होता है, लेकिन महिलाओं में कैंसर के मामले और मृत्यु दर ज्यादा रहती है.

नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली लगभग 69 लाख मौतें रोकी जा सकती थीं और 40.3 लाख

महिलाओं का इलाज किया जा सकता था. वैश्विक स्तर पर कैंसर के नए मामलों में 48% महिलाएं होती हैं और कैंसर से होने वाली मौतों में 44% महिलाएं शामिल हैं. ऐसा तब होता है, जब महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर व सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है और उसे इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है. चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाएं जानकारी के अभाव, फाइनेंशियल पावर और प्राइमरी सर्विसेज की उपलब्धता की कमी के कारण सही समय पर और उचित इलाज नहीं करवा पाती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चाहे महिलाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहती हों और समाज के किसी भी तबके से आती हों, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जानकारी और निर्णय लेने की शक्ति की कमी होने की संभावना अधिक होती है.

इस बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
नई दिल्ली एम्स के ओन्कोलॉजि डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक शंकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कैंसर देखभाल में निश्चित रूप से जेंडर एक बड़ा फैक्टर होता है. गरीब महिलाओं को इस बारे में हेल्थकेयर को लेकर काफी कम जानकारी है. इसका असर महिलाओं पर पड़ता है. धूम्रपान और तंबाकू के संपर्क में आने वाले महिला और पुरुष दोनों को कुछ कैंसर का खतरा बराबर होता है, लेकिन महिलाओं का इलाज प्राथमिकता नहीं है. यही कारण है कि उनकी कंडीशन

बदतर हो जाती है. कैंसर और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी के अलावा, सामाजिक बदलाव की भी जरूरत है. महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर है. इन कैंसर को इलाज के जरिए रोका जा सकता है. हालांकि महिलाएं इन समस्याओं को लेकर पुरुष डॉक्टरों के पास जाने से झिझकती हैं या महिला डॉक्टर से प्राइवेट पार्ट की जांच करने से भी हिचकिचाती हैं, जिससे इलाज में देरी होती है.

महिलाएं करें 5 काम, कैंसर की होगी रोकथाम

- सभी महिलाओं को हर महीने अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करनी चाहिए और साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए.
- 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए साल में एक बार मैमोग्राफी (mammography) करवानी चाहिए.
- जिन महिलाओं को सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान ब्रेस्ट में किसी गांठ का पता चलता है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करा चाहिए.
- सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए 25 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं को पैप स्मीयर परीक्षण (pap smear test) करवाना चाहिए.
- महिलाओं को मानव पैपिलोमा वायरस का पता लगाने के लिए हर 5 या 10 साल में एचपीवी परीक्षण (HPV test) करवाना चाहिए.

यूपी गेट पर धरने पर बैठे लोग , लगा लंबा जाम; दिल्ली और गाजियाबाद की पुलिस मौके

परिवहन विशेष न्यूज

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी गाजियाबाद से दिल्ली कूच किए लेकिन पुलिस ने सभी को यूपी गेट के पास ही रोक लिया। यूपी गेट के फ्लाईओवर के नीचे के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस कारण लिंक रोड पर लंबा जाम लग गया है। प्रदर्शनकारी वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं।

गाजियाबाद। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे लोगों पुलिस ने यूपी गेट पर रोक लिया है। सभी लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। यूपी गेट पर फ्लाईओवर के नीचे के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस कारण लिंक रोड पर लंबा जाम लग गया है। मौके पर दिल्ली और गाजियाबाद की पुलिस मौजूद है। प्रदर्शनकारियों में काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं।



पिछले सत्र में कक्षा एक से आठ तक 110 छात्रों का था नामांकन

ग्रेटर नोएडा में जर्जर भवन के डर से 100 छात्रों ने छोड़ा स्कूल, हर रोज छत से गिर रहा प्लास्टर

परिवहन विशेष न्यूज

दनकौर ब्लॉक में संचालित उच्च प्राथमिक स्कूल डेरी खूबन की जर्जर इमारत के डर से पिछले चार सालों में 100 से अधिक छात्रों ने नाम कटवा लिया है। शासन स्तर से लगातार मिशन कायाकल्प की निगरानी हो रही है लेकिन जिम्मेदारों को यह स्कूल नजर नहीं आ रहा है। स्कूल की कोई भी ऐसी कक्षा नहीं बची है जिसकी छत से प्लास्टर गिर न रहा हो।

ग्रेटर नोएडा। प्रदेश सरकार परिषदीय स्कूलों में लगातार सुधार का दावा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी से सटे प्रदेश के हाइटैक जिलों में शामिल गौतमबुद्धनगर में ही स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है।

दनकौर ब्लॉक में संचालित उच्च प्राथमिक स्कूल डेरी खूबन की जर्जर इमारत के डर से पिछले चार सालों में 100 से अधिक छात्रों ने नाम कटवा लिया है। शासन स्तर से लगातार मिशन कायाकल्प की निगरानी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों को यह स्कूल नजर नहीं आ रहा है। कभी स्कूल में 170 से 180 तक छात्रों का नामांकन हुआ करता था, लेकिन स्कूल में कोई सुविधा नहीं होने के कारण अब 77 छात्र ही बचे हैं। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि सत्र 2021-22 में 110 छात्र संख्या थी।

कई बार विभाग को अवगत कराया गया कि स्कूल की हालत खराब होने के कारण लगातार छात्र अपने नाम कटवा रहे हैं। उसके बाद भी कोई

सुनवाई नहीं हुई। ब्लैकबोर्ड खराब हो चुके हैं। ब्लैकबोर्ड की दीवार से पपड़ी गिर रही है। छात्रों को अपने पास बुलाकर काफी में पढ़ाना पड़ रहा है।

हर रोज छत से गिर रहा प्लास्टर

स्कूल की कोई भी ऐसी कक्षा नहीं बची है, जिसकी छत से प्लास्टर गिर न रहा हो। छात्रों को पढ़ाते समय अचानक तेज आवाज आती है। तब पता चलता है कि दूसरी कक्षा का प्लास्टर गिर गया है। दो दिन पहले बरामदे की छत का प्लास्टर गिर गया था। गनीमत यह हुई कि कुछ देर पहले से छात्र लंच करके वहां से हट थे।

कंपोजिट ग्रांट के रूप में मिले दो लाख रुपये

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल को पिछले चार साल में दो लाख रुपये कंपोजिट ग्रांट के रूप में मिले। 100 से 250 छात्र संख्या पर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष ग्रांट मिलता है।

कंपोजिट ग्रांट से शिक्षक स्कूलों में स्वच्छता और हैंडवाशिंग, शौचालय की क्रियाशीलता, शुद्ध पेयजल, शिक्षण सहायक सामग्री, फर्स्ट एड बाक्स, अग्निशमन यंत्र आवश्यकतानुसार रंगाई-पुताई, स्टेनरी, चटाई और टाट-पट्टी आदि का कार्य करा सकते हैं।

गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की ओर से कोई कार्य नहीं कराया गया है। स्कूल प्रशासन की ओर से यदि कंपोजिट ग्रांट का उपयोग किया जाता तो स्कूल की हालत इतनी खराब नहीं होती।



यमुना प्राधिकरण

को कराना है कायाकल्प

उच्च प्राथमिक स्कूल डेरी खूबन यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। यमुना प्राधिकरण को सीएसआर फंड की मदद से स्कूल में कायाकल्प का कार्य कराना है, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी छात्रों को मौत के मुंह में छोड़ चुके हैं। तीन साल से केवल स्कूल में कार्य कराने का एस्टीमेट तैयार कागजों में तैयार कर रहे हैं।

एक भी छात्र यूनिफार्म में नहीं पहुंचता स्कूल

कक्षा एक से आठवीं तक संचालित स्कूल का एक भी छात्र यूनिफार्म में नहीं आता है। छात्रों ने बताया कि यूनिफार्म के 1200 रुपये अभी तक नहीं आए हैं। वहीं शिक्षकों ने बताया कि 10 प्रतिशत छात्र ही यूनिफार्म में आते हैं। शिक्षकों की

लापरवाही का भी नतीजा है कि एक भी छात्रों के अभिभावकों ने यूनिफार्म नहीं खरीदी।

स्कूल में नहीं आई कभी बिजली

देश के सूरूर इलाकों में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन जेवर विधानसभा के इस स्कूल में कभी बिजली ही नहीं आई। सर्दी, गर्मी और वर्षा के मौसम में छात्रों को बिना बिजली के ही पढ़ाई करनी होती है। बिजली नहीं होने से गर्मी में छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।

कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में लगातार कार्य कराएं जा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के सीईओ से कार्य कराने के लिए आग्रह किया गया है। उन्होंने जल्द कार्य कराने के लिए कहा है। कंपोजिट ग्रांट को भी शिक्षकों को खर्च करना चाहिए।

ऐश्वर्या लक्ष्मी, बेसिक शिक्षा अधिकारी

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 112 स्कूलों की सूची दी गई थी। सभी स्कूलों में कायाकल्प अभियान के तहत कार्य करा दिए गए हैं। कुछ गांव के स्कूलों की हालत सही नहीं थी। यमुना प्राधिकरण ने अब उन गांवों के स्कूलों में भी कायाकल्प के तहत कार्य कराने का निर्णय लिया है।

- डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

ट्रांसफॉर्मर में लगी भीषण आग, चपेट में आई पास खड़ी चार कारें; जलकर हुई राख



गाजियाबाद जिले में ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग इतनी तेज थी कि आसपास खड़ी चार कारें भी उसकी चपेट में आ गईं। यह घटना डीएलएफ चौकी क्षेत्र

शालीमार गार्डन में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची लेकिन तब तक चार कारें जल चुकी थीं। आग पर काबू पाया गया। आग से कोई हताहत नहीं है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से

लाखों का नुकसान हो गया। आग इतनी तेज थी कि आसपास खड़ी चार कारें भी उसकी चपेट में आ गईं। यह घटना डीएलएफ चौकी क्षेत्र शालीमार गार्डन में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक चार कारें जल चुकी थीं। आग पर काबू पाया गया। आग से कोई हताहत नहीं है।

नौकरशाहों की राजनीति में बढ़ती रुचि सेवा से प्रेरित तो कतई नहीं है

ललित गर्ग

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगमियां उभार पर हैं। इस बार वहां चुनावी घमासान में अपना भविष्य आजमाने वाले अफसरों की सूची पर नजर डालें तो निशा बांदे डिप्टी कलेक्टर सबसे ऊपर हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर एमपी वरकडे के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना है।

पांच राज्यों के विधानसभा एवं अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अनेक प्रशासनिक अधिकारी राजनीति में आने के लिये अपने पदों से इस्तिफा दे रहे हैं। इन प्रशासनिक अधिकारियों को नौकरशाही की तुलना में राजनीति इतनी लुभावनी क्यों लग रही है, क्यों राजनीति के प्रति इन नौकरशाहों में आकर्षण बढ़ रहा है? इन्हीं प्रश्नों के बीच अहम प्रश्न है कि आईएएस अधिकारी वी.के. पांडेयन द्वारा सर्वोच्च रिटायरमेंट एवं मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर निशा बांग्रे का इस्तीफा मंजूर होने की खबर एवं उनके राजनीतिक दलों से जुड़कर चुनाव लड़ना लोकतंत्र को किस मोड़ पर ले जायेगा। इनके अतिरिक्त भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आईएफएस, डॉक्टर, प्रोफेसर आईपीएस अफसर आदि अनेक नौकरशाह राजनीति में अपना भविष्य आजमाने को तत्पर हैं। लोकशाही और नौकरशाही निश्चय ही लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तम्भ हैं। दोनों के कंधों पर लोकतंत्र की सफलता एवं राष्ट्र-निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देशहित का जज्बा ही दिखाना है तो क्या नौकरशाह में यह संभव नहीं है? ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका

दोनों का जीवन अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरा रहता है। इन दोनों की सारी नीतियों में, सारे निर्णयों में, व्यवहारों में, कथनों में गहरा विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित है। यही कारण है कि सत्य एवं सत्ताबनाएं खोजने से भी नहीं मिलती, इनका व्यवहार दोगला हो गया है। दोहरे मापदण्ड अपनाने से उनकी हठ नीति, हर निर्णय समाधानों से ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पांडेयन और निशा के इन फैसलों से कई संवाल खड़े हुए हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

नौकरशाहों की राजनीति की ओर बढ़ने की होड़ सेवा प्रेरित तो कतई नहीं है। यह अधिक से और अधिक पाने की भूख है जो नौकरशाही की तरह राजनीति को भी अधिक भ्रष्ट ही करेगी। यह सर्वविदित है कि देश की प्रशासनिक संस्थाएं किस कदर साख एवं समझ के संकट से जूझ रही हैं? उन पर राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप निराधार नहीं है। यह न तो देश के हित में है और न लोकतंत्र के। ऐसे में, पांडेयन और निशा जैसे उदाहरणों से नौकरशाही की विश्वसनीयता को और लड़ना संविधान तय मानदंडों के तहत अपने हरेक नागरिक को अवसर की स्वतंत्रता देता है, और इस लिहाज से अफसरों के राजनीति में आने में कुछ गलत नहीं है, मगर इन दिनों जिस तरह नौकरशाहों में ऐसा राजनेताओं के कृपापात्र बनने और पुरस्कृत होने की

प्रवृत्ति गहराती जा रही है, उसमें पांडेयन एवं निशा जैसे तरक्की पसन्द, महत्वाकांक्षी एवं लालची अफसरों का राजनीतिक में घुसपैठ का मुद्दा अन्य नौकरशाहों को भी सत्ताधीशों से सांठ-गांठ के लिए प्रेरित करेगा। इससे प्रशासनिक क्षेत्र में अजीब ऊहापोह एवं अस्थिरता बनेगी। जरूरत इस बात की है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संविधान ने जो उम्मीदें पाली हैं, उन पर वे खरी उतर सकें और हम आदर्श लोकतंत्र के रूप में दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकें।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगमियां उभार पर हैं। इस बार वहां चुनावी घमासान में अपना भविष्य आजमाने वाले अफसरों की सूची पर नजर डालें तो निशा बांदे डिप्टी कलेक्टर सबसे ऊपर हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर एमपी वरकडे के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना है। वरद मूर्ति मिश्रा आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं, सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। वी.के. बाथम रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इनके भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। वी. चंद्रशेखर, किरण अहिरवार, अजिता वाजपेयी पांडे, हीरालाल त्रिवेदी, पन्नालाल सोलंकी, पवन जैन, गाजी राम मीणा, आजाद सिंह डबास आदि अनेक अफसरों के नाम हैं जिनके अब सक्रिय रूप से विकास और पेट्रोलियम विभाग हैं, जबकि आर.के. सिंह बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं और अर्जुन राम मेघवाल (आईएएस 1999-बैच) कानून और न्याय, संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री (एमओएस) हैं। मेघवाल राजस्थान बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। वहीं, सोमप्रकाश (आईएएस 1988-बैच) वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। पूर्व सिविल सेवक भी अब प्रमुख भाजपा की संगठनात्मक भूमिकाओं में कदम रख रहे हैं जो पहले के डेरों के लिए आरक्षित थे। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के रूप में के. अन्नामलाई (आईपीएस 2011-बैच) की नियुक्ति देखी जा सकती है। दूसरा उदाहरण रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओ.पी. चौधरी (आईएएस 2005-बैच)

अधिकारियों के दोनों हाथों में रेवडियां हैं- पहले नौकरशाह के रूप में और अब राजनेता के रूप में। आजादी के अमृतकाल में पहुंचने तक विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐसे नौकरशाह रहे हैं जिन्होंने उच्च सरकारी पदों को छोड़ उच्च राजनीतिक पदों पर रहे हैं। नटवर सिंह, मणिशंकर अय्यर, मीरा कुमार, अजीत जोगी, यशवंत सिन्हा आदि पूर्व में मंत्री रहे हैं तो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी सरकार में अश्विनी वैष्णव (आईएएस 1994-बैच), केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और उनके पास रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे तीन बड़े विभाग हैं। जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया, इसी तरह, हरदीप सिंह पुरी के पास शहरी विकास और पेट्रोलियम विभाग हैं, जबकि आर.के. सिंह बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं और अर्जुन राम मेघवाल (आईएएस 1999-बैच) कानून और न्याय, संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री (एमओएस) हैं। मेघवाल राजस्थान बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। वहीं, सोमप्रकाश (आईएएस 1988-बैच) वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। पूर्व सिविल सेवक भी अब प्रमुख भाजपा की संगठनात्मक भूमिकाओं में कदम रख रहे हैं जो पहले के डेरों के लिए आरक्षित थे। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के रूप में के. अन्नामलाई (आईपीएस 2011-बैच) की नियुक्ति देखी जा सकती है। दूसरा उदाहरण रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओ.पी. चौधरी (आईएएस 2005-बैच)

अपनी प्रतिभा-कौशल का लाभ देश को दे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सत्ताधीशों और नौकरशाहों के गठजोड़ ने न सिर्फ राजनीति को विदूष किया है, बल्कि शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें इसके कारण गहरी हुई हैं। ऐसे में, निशा एवं पांडेयन जैसे लोगों के राजनीति में सक्रिय होने से क्या वर्षों से जनसेवा में जुटे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं होगा? क्या नौकरशाहों की वरीयता लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप है? क्या यह राजनीति में एक नये तरह के असंतोष एवं विद्रोह को नहीं पनपायेगी? पांडेयन और निशा का राजनीति में आने का फैसला जनसेवा से प्रेरित है या लोभ एवं महत्वाकांक्षाओं की परिणति? यदि उन्हें राजनीति में इतनी ही दिलचस्पी थी, तो प्रशासन में इतने वर्ष खर्च क्यों किए? क्यों नहीं प्रशासन में रहते हुए देश के लिये कुछ अनूठा करके दिखाया। राजनेताओं से भी अधिक अपेक्षाएं नौकरशाहों से की जाती हैं, यदि वे चाहते तो जनोपेक्षाओं खरे उतरते। लेकिन उनके द्वारा जनाकांक्षाओं को किनारे किया जाता रहा है और विस्मय है इस बात को लेकर कि वे चिंतित या शर्मसार भी नजर नहीं आए। जो राजनीतिक शिखर पर हो रहा है उसी खेल का विस्तार आज हमारे प्रशासन के आस-पास भी दिखाई देता है। उससे भी ज्यादा विस्मय यह है कि दूसरों पर सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को गलत बता रहे हैं और नौकरशाह खुद उन्हें जगाने का मुखौटा पहनते हाथ जोड़कर सेवक बनने का अभिनय कर रहे हैं।

बाइक के स्पार्क प्लग का ऐसे रखें खयाल नहीं तो बीच रास्ते में मिल सकता है धोखा



अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और उसके स्पार्क प्लग में कचरा या तेल के अवशेष आ गए हैं तो इस समस्या को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी बाइक के साथ मिली टूल किट में से प्लग पाना

निकालना होगा। उसके बाद बाइक के स्पार्क प्लग को खोल लीजिये और उसे पहले मिट्टी के तेल या पेट्रोल से सावधानी से धोएं।

नई दिल्ली। अगर आपके पास भी मोटरसाइकिल है तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बाइक के इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, जो बाइक

को स्टार्ट करने में मदद करता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में आप अपने मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग की देखभाल जरूर करें। आइये जानते हैं स्पार्क प्लग की देखभाल करने के तरीकों के बारे में।

स्पार्क प्लग की सफाई जरूरी

सबसे पहले स्पार्क प्लग की सफाई नियमित तौर पर करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि स्पार्क प्लग की सफाई कैसे करें, तो इसका जवाब आपको नीचे मिलने वाला है।

ऐसे करें स्पार्क प्लग की सफाई

अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और उसके स्पार्क प्लग में कचरा या तेल के अवशेष आ गए हैं, तो इस समस्या को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी बाइक के साथ मिली टूल किट में से प्लग पाना निकालना होगा। उसके बाद आप बाइक के स्पार्क प्लग को खोल लीजिये और उसे पहले मिट्टी के तेल या पेट्रोल से सावधानी से धोएं। इसके अलावा किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ें या

हल्के मोटे रेगमाल से साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बाइक का स्पार्क प्लग साफ हो जाएगा और उस पर जर्मी गंदगी हट जाएगी।

अब बारी आती है बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की। बाइक स्टार्ट करने से पहले स्पार्क प्लग को अपनी जगह से टाइटली फिट कर दें। स्पार्ग प्लग लगाने के बाद बाइक को किक से स्टार्ट कीजिए आप देखेंगे की आपकी बाइक आसानी से स्टार्ट हो जाएगी।

मोटरसाइकिल के फिल्टर को साफ रखने के लिए अपनाएं ये तरीका

एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पर चलाना चाहिए ये उस जगह पर डिपेंड करता है जहां आप रहते हैं। बहुत से लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां उनका सामना रोज कच्ची सड़कों से होता है तो ऐसी जगह पर एयर फिल्टर जल्दी जाम हो जाते हैं। वहीं अगर आप हाइवे या फिर एक्सप्रेसवे पर रहते हैं तो एयर फिल्टर की आयु अधिक होती है।



नई दिल्ली। प्रत्येक वाहन मालिकों को वाहन की नियमित देखरेख करना बेहद जरूरी होता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर है। कई बार बाइक माइलेज इस वजह से भी नहीं देती है क्योंकि बाइक का एयर फिल्टर खराब हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बाइक के साइलेंसर से बीच-बीच में पटाखे जैसी आवाज न आए और बाइक अच्छी माइलेज दे तो आप एक निश्चित समय पर फिल्टर को साफ करवा लें या फिर उसे चेज कर लें। अब सवाल उठता है कि कितने किलोमीटर पर एयर फिल्टर चेज करवाने की जरूरत पड़ती है तो इसका जवाब आपको इस ऑर्टिकल के माध्यम से मिलने वाला है।

कितने किलोमीटर पर बदलवाना चाहिए एयर फिल्टर ?

एयर फिल्टर कितने किलोमीटर पर चलाना चाहिए ये उस जगह पर डिपेंड करता है, जहां आप रहते हैं। बहुत से लोग ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां उनका सामना रोज कच्ची सड़कों से होता है तो ऐसी जगह पर एयर फिल्टर जल्दी जाम हो जाते हैं। वहीं अगर आप हाइवे या फिर एक्सप्रेसवे पर रहते हैं तो एयर फिल्टर की आयु अधिक होती है। कई बार अधिक फैक्ट्री वाले इलाकों में भी रहने पर उसका असर बाइक के फिल्टर पर पड़ता है। एक्सपर्ट की मानें तो एयर फिल्टर को वाहन मालिक 20000 किमी के बाद चेज कर सकते हैं। हालांकि, उससे पहले वाहन मालिक अपने गाड़ी के एयर फिल्टर की सफाई खुद से कर सकते हैं।

घर पर कैसे करें एयर फिल्टर को साफ ?

सबसे पहले आप अपने मोटरसाइकिल के सीट को खोलकर कर उसके नीचे लगे एयर फिल्टर को बाहर निकालें। उसके बाद एयर प्रेशर के माध्यम से आप जितना हो सके बाहर लगी चिपकी हुई गंदगी को झाड़ दें। उसके बाद एयर फिल्टर क्लीनर लगाएं और सैम्पू से या फिर किसी अन्य घोल से फिल्टर पर ब्रश से रगड़ें। अब इसके बाद इसे साफ पानी से पूरी तरह से धो लें। धोने के बाद आपको एयर फिल्टर से पानी पूरी तरह से निचोड़ना होगा। एयर फिल्टर को कुछ देर तक सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद उस साफ एयर फिल्टर को फिर से उसी जगह पर फिट कर दें, जहां से उसे निकाला गया था।

होंडा शाइन 100 कितनी खास ? 5 आसान प्वाइंट्स में समझें

बिल्ड क्वालिटी इसकी अपने राइवल्स के कंपैरिजन में 19-20 है एचएफ डिलक्स और प्लेटिना के आस पास इसकी बिल्ड क्वालिटी है लेकिन स्प्लेंडर के कंपैरिजन में ये पीछे है। प्राइस प्वाइंट को कंपीटेटिव रखने के लिए इसमें थोड़े बहुत कॉस्ट कटिंग आप देख सकते हैं। इसमें 98.98 सीसी 4 स्ट्रोक एसआई इंजन मिलता है। आइये डिटेल में जानते हैं।

नई दिल्ली। अगर आप भी होंडा शाइन 100 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। क्योंकि इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं होंडा शाइन 100 से जुड़े 5 बड़ी बातों के बारे में।

रात के समय चलाने में कैसी है ?

इस बाइक को रात के समय चलाने में शायद उतना मजा न आए, इसमें हाइलोजन हेडलैप और प्रोजेक्टर लैप दिया गया है, जो ठीक-ठीक लाइट देती हैं, लेकिन एलईडी के कंपैरिजन में थोड़ी कम बिजबिलिटी मिलती है। हालांकि प्राइस प्वाइंट के हिसाब से देखा जाए तो राइडर के जरूरत के हिसाब से बिजबिलिटी मिल जाती है। 9 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और माइलेज भी अच्छा है तो रात के समय कहीं फंसने की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी।

कितना दमदार है इसका इंजन ?

इसमें 98.98 सीसी, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन मिलता है। इसका इंजन ई20 और ओबीडी 2 कंप्लायंट को सपोर्ट करती है। 7.38 हॉर्स पावर मिलता है, जो Hero Splendor और HX Deluxe से 0.6 एचपी कम है। पर इसका 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क इन दोनों के समान है।

कैसी है बिल्ड क्वालिटी

बिल्ड क्वालिटी इसकी अपने राइवल्स के कंपैरिजन में 19-20 है, एचएफ डिलक्स और प्लेटिना के आस पास इसकी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन स्प्लेंडर के कंपैरिजन में ये पीछे है। प्राइस प्वाइंट को कंपीटेटिव रखने के लिए इसमें थोड़े बहुत कॉस्ट कटिंग आप देख सकते हैं।

कीमत और राइवल्स

100 सीसी में इस बाइक के सामने कई राइवल्स है, जिसमें देश में सबसे अधिक बिकने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर का नाम शामिल है।

हीरो एचएफ डिलक्स- 55,021 एक्स-शोरूम
होंडा शाइन- 65 हजार एक्स-शोरूम
प्लैटिना-- 65,251 एक्स-शोरूम
स्प्लेंडर प्लस-- 71,632 एक्स-शोरूम से शुरू
टीवीएस स्पोर्ट 110 सीसी- 61,602 एक्स-शोरूम से शुरू

गाड़ियों में 360 कैमरा सेटअप होना कितना जरूरी ? जानें इसके फायदे



360 डिग्री कैमरा सेटअप गाड़ी के अलग अलग हिस्सों में कुछ कैमरा एक सॉफ्टवेयर के जरिए पेयर्ड होते हैं जो कार के आसपास की गतिविधियों को एक सिंगल स्क्रीन पर आपके सामने लाकर रख देता है। 360 डिग्री कैमरा सेटअप में कम से कम 4 कैमरे होते हैं जिनमें से एक फ्रंट और एक रियर बंपर पर और दो साइड मिरर पर लगे होते हैं।

नई दिल्ली। आजकल की गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा

सेटअप आना आम हो रहा है। अगर आप 10 लाख से ऊपर बजट की कार लेते हैं तो उनमें ये फीचर्स आपको अधिकतर गाड़ियों में मिल जाएंगे। इस ऑर्टिकल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं 360 डिग्री कैमरा और उससे होने वाले फायदों के बारे में।

ट्रैफिक में मिलती है मदद

सड़क पर इतनी गाड़ियां चलने लगी हैं कि ट्रैफिक होना आम बात हो गया है। ट्रैफिक के दौरान हर कोई आगे निकलने की जद्दोजहत पर लगा रहता है, ऐसे में कई बार गाड़ी में स्कैन आ जाता है। ऐसी कंडिशन में अगर आपके गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप लगा हुआ रहता है तो ये आपके काफी हेल्प करता है। आप गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे बाहर चल रही

चारों तरफ की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं।

360 डिग्री कैमरा कैसे करता है काम ?

360 डिग्री कैमरा सेटअप गाड़ी के अलग अलग हिस्सों में कुछ कैमरा एक सॉफ्टवेयर के जरिए पेयर्ड होते हैं जो कार के आसपास की गतिविधियों को एक सिंगल स्क्रीन पर आपके सामने लाकर रख देता है। 360 डिग्री कैमरा सेटअप में कम से कम 4 कैमरे होते हैं, जिनमें से एक फ्रंट और एक रियर बंपर पर और दो साइड मिरर पर लगे होते हैं। इस सभी कैमरे का विजुअल जब साथ में दिखाई देता है तो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे गाड़ी के चारों तरफ का नजारा देखने में सक्षम होता है। हालांकि, कुछ महंगी गाड़ियों में 6 कैमरे पाए जाते हैं।

मारुति का नेट प्रॉफिट 80 प्रतिशत बढ़ा, दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे से कंपनी के शेयर में रिकॉर्ड बढ़त



सितंबर तिमाही नतीजों का दौर अभी भी जारी है। Maruti Suzuki ने सितंबर तिमाही नतीजों का एलान किया है। इस तिमाही कंपनी का नेट प्रॉफिट 80 फीसदी बढ़ गया है। गाड़ी की बेहतर बिक्री कमोडिटी कीमतों में नरमी लागत में कमी के प्रयासों और उच्च गैर-परिचालन की वजह से कंपनी के मुनाफा में बढ़ोतरी आई है।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया ने शुक्रवार को तिमाही नतीजों का एलान

किया है। कंपनी के द्वारा बनाई जाने वाली गाड़ी बेहतर बिक्री, कमोडिटी कीमतों में नरमी, लागत में कमी के प्रयासों और उच्च गैर-परिचालन ने कंपनी की इनकम को बढ़ाया है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के जुलाई-सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट में 80.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। अब यह 3,716.5 करोड़ रुपये हो गई है।

मारुति सुजुकी के तिमाही नतीजे

मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने दूसरी तिमाही में 2,061.5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। इसके अलावा कंपनी ने अधिक बिक्री और प्रोडक्श की वजह से 35,535.1 करोड़ रुपये की नेट सेल दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट सेल 28,543.50 करोड़ रुपये था। कंपनी ने सितंबर को खत्म तिमाही के दौरान 5,52,055 वाहन

बेचे, जबकि पिछले साल की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 5,17,395 यूनिट था। कंपनी ने कहा कि इस साल जुलाई-सितंबर की अवधि में 5,52,055 वाहनों में से 4,82,731 यूनिट घरेलू बाजार में बेची गईं। वहीं, बाकी के 69,324 यूनिट को निर्यात किया गया। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने यह भी कहा कि इस तिमाही में अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री और नेट प्रॉफिट दर्ज किया है।

कंपनी के शेयर में आई तेजी

आज सुबह कंपनी के शेयर 10,479.30 रुपये प्रति शेयर पर खुला था। इसके बाद कंपनी के शेयर में उतार-चढ़ाव जारी रहा। वहीं बाजार बंद होते समय मारुति सुजुकी के शेयर 107.30 अंको की बढ़त के साथ 10,531.45 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

जाति के जंजाल से आखिर क्यों बाहर नहीं निकलना चाहता भारतीय समाज?

राकेश सैन

यह संयोग ही है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तभी जातीय जनगणना के नाम पर जातिवाद राजनीति का जह हो गई है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये जाति आखिर क्यों नहीं जाती? इसको लेकर हमारे स्वाधीनता सेनानी क्या सोचते थे। स्वामीनार भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। इससे पहले देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में स्पष्ट कहा था कि जातियों की गिनती नहीं होनी चाहिए। उनका भविष्य में किसी जातिगत जनगणना नहीं होगा। उनके बाद एचएम पटेल, वाईबी चव्हाण और ज्ञानी जैल सिंह केद्रीय गृहमंत्री बने। विहार के नेता बापी मंडल ने इन तीनों गृह मंत्रियों को जातियों की गणना कराने की मांग करते हुए पत्र लिखे थे, पर किसी ने पटेल के निर्णय को चलटना उचित नहीं समझा। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी के उल्लेख का जिक्र किया जा सकता है, जो 'यंग इंडिया' के 1 मई, 1930 के अंक में छपा था। इसमें गांधी जी ने लिखा है, 'मेरे, हमारे, अपनों के स्वराज में जाति और धर्म के आधार पर भेद का कोई स्थान नहीं हो सकता। स्वराज सबके लिए, धर्म के कल्याण के लिए होगा।'

बापू की इस भावना का संविधान सभा ने भी ध्यान रखा। लेकिन आजादी के बाद जैसे-जैसे जातीय गोलबंदी की राजनीति तेज हो गई, बापू के इन शब्दों का प्रभाव कम होने लगा और जाति अपने-अपने खांचे में और मजबूत होने का राजनीतिक खराब देखने लगी। आधारी गोलबंदी की राजनीति को जाति आधारित जनगणना में अपनी राह दिखने लगी। आश्चर्य नहीं कि पिछड़े वर्गों की स्थिति पर 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले बीपी मंडल ने भी यह मांग सामने रखी। यह बाबा और है ही तब के यहूदी मंत्री जानी जैल सिंह ने इसे नामंजूर कर दिया था। अंग्रेजों ने 1931 में जो जनगणना कराई, जिसका आधार जाति वैमनस्य फैलाना भी था। आजादी के बाद जब 1951 की जनगणना की नैयारियां हो रही थीं, तब भी जाति जनगणना की मांग उठी। लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने इसे खारिज कर दिया। पटेल ने कहा था, 'जाति जनगणना देश के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ सकती है।'



इसका समर्थन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, डॉ. बीआर आंबेडकर और मौलाना आजाद ने भी किया। इसके पहले संविधान सभा की एक बस में भी पटेल गांधी जी के विचारों के मुताबिक आगे बढ़ने की मंशा जताते हुए जाति आधारित आरक्षण की मांग को खारिज कर चुके थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सिर्फ राजनीति की आंदोलन नहीं था। उसमें सामाजिक सुधार के भी मूल्य निहित थे। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भावी भारत का सपना देखा, उसमें जातिवाद की गुंजाइश नहीं थी। संविधान और कानून के सामने सभी की बराबरी थी। हालांकि आजादी के बाद विशेषकर समाजवादी धारा की राजनीति जैसे-जैसे आगे बढ़ी, प्रोपक्ष रूप से जातिवादी राजनीति को ही बढ़ावा देती रही। डॉक्टर लोहिया जाति तोड़ने की बात करते थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनके नारे को सतही तौर पर स्वीकार किया। लोहिया मानते थे कि आर्थिक बराबरी होते ही जाति व्यवस्था खत्म तो होगी ही, सामाजिक बराबरी भी स्थापित हो जाएगी।

मोका देखा। हर जाति राजनीतिक अधिकार पाने के लिए अपने खोल को मजबूत करने में जुटा गया। यह उलटबांसी ही है कि जिस जयप्रकाश आंदोलन से निकली गैर-कांग्रेसी सरकार ने मंडल आयोग गठित किया, उस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के गांव सिताबदिया में 1974 में हुई एक बैठक में जातिवादो व्यवस्था तोड़ने की दिशा में गंभीर प्रयास करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तब जयप्रकाश ने नारा दिया था, 'जाति छोड़ो, पवित्र भाग लो, इसका को ईसान से जोड़ो।' जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस प्रयासों में तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि जाति तोड़ने की बात करने वाले राजनीतिक अधिकारशानुयायी जातियों की गोलबंदी में अपना भविष्य देख रहे थे। इसका आभास चंद्रशेखर को था, इसलिए उन्होंने जयप्रकाश से आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में आंदोलनकारी अपनी-अपनी जातियों के नेता के तौर पर पहचाने जाएंगे। जातीय गोलबंदी को और आक्रामक रूप बाबू कौशिक ने दिया। उनका नारा था, 'जिसकी जातिनी संख्या भारी, उसकी उतनी

हिस्सेदारी ।'

वर्तमान जातीय जनगणना की जिद्द भी इसी सोच का विस्तार है। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि इससे सामाजिक न्याय मिलना संभव होगा। जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्रीय सूची में पिछड़ी जातियों का कुल संख्या 2633 है। देश में जाति आधारित जनगणना होती है तो ये जातियां अपने-अपने खोल समजूत करके में जुट जाएंगी क्योंकि इन सभी जातियों के नेताओं को अधिक से अधिक हिस्सेदारी की उम्मीद होगी। जातिगत लाभभरी के दौरान राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द आदि आदर्श स्थिति का क्या होगा इसका अनुमान लगाना अधिक मुश्किल नहीं है। आश्चर्य की बात है कि नीतिश कुमार व लालू प्रसाद यादव जैसे लोकहिवावादी नेताओं के जातिवादी भाँपू में अब कांग्रेस के भी मिले-जुलें स्वर सुनाई देते हैं, ये वही कांग्रेस है जिनके नेता गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कभी जातिवादी जनगणना को खतरनाक बताया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल की जातिवादी राजनीति देश व समाज के लिए घातक ही साबित होगी।

संपादक की कलम से

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के द्वारा

हिमाचल कर्मचारियों के हितों का
इसका है और इसीलिए प्रदेश के संसाधन
मन्त्र वहाँ पूनीय-वन्दनीय बना देते हैं।
कमोवेशर सरकार को अपने संसाधनों
से इसी प्रक्रिया में खुद को अक्ल साबित
करने के लिए सामग्री मुँहों पड़ती है।
राज्य के कर्मचारियों को इतनी तब जाह
दे डाली है कि अब राजनीति के डाली-
डाली इनके प्रति दुखी होती है। ओख
पैशन को गोड मान खाल कर सता में
अंश का औपम्य प्रशासक ट्रिब्यूनल
के रास्ते कर्मचारी वर्ग के अधिकारों को
न्यूनता दे रही है। प्रशासक ट्रिब्यूनल
एक तरह की सिपायि रस्साकशी बना
है। कर्मचारी वर्ग को कानूनी बत
दिलाने के लिए बार-बार इसके दरवाजे
खोले जाते हैं या फिर सारे दांव या
कानूनी पोंते अदालत में ब्याप्त संबोधित
कराए जाते हैं। पक्वतों पर्याप्त संस्कारों ने
कर्मचारी कवच को प्रासासिक
ट्रिब्यूनल से उखाड़कर माननीय
अदालत के दरवाजे तक पहुंचा दिया।
उस समय इक्कीस हजार कर्मचारी
मामलों का देह ज अदालत के दरवाजे
पहुंच गया था और अब फिर क्वापद यह
इस विषय को स्वतंत्र ट्रिब्यूनल के
अधीन लया जाए। दोनों ही तरह के
फैसलों के तर्क कर्मचारी वर्ग के लिलज

सहचलपूर्ण रहेंगे, फिर भी हथपरीस्थित के संकेत, निर्णयों की गति तथा नए मामलों की प्राप्ति आदि आती है। कमचारी मामलों के संदर्भ प्रायः ट्रांसफर पालिसी न होने के कारणों से स्टरकाते हैं। वेवन विसंगतियों, स्त्रोन्त होने के मजले कोटों से संबंधित मामले जस इक होइ, तो इन्हें निपटाने का दमव पड़िया सगइता है। जाहिर है प्रशासनिक ट्रिब्यूल की स्थापना का उद्देश्य तथाऐसी पद्धति के कार्यन्वयन से सहजता व सरलता का तकाजा दिखाई देना है, लेकिन व्यवहारिकता के प्रश्न पर कानून के स्वरूपत बदल जाते हैं।

वही कानून अदालत की परिपाटी में अपनी परंपरा और निष्पक्षता की दृढ़ता से विश्वास तो पैदा करता है, लेकिन कर्मचारी मामलों के निपटारे समयावधि में तय नहीं करते। इसके विपरीत प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की सार्थकता कानून की गतिशीलता व विकेंद्रीकरण स्पष्ट है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अपनी परिपाटी में मंडी व धर्मशाला की संकीर्ण

बैच के जीएन न केवल कर्मचारी वर्ग के नजदीक पहुंचती है, बल्कि व्याप्य पाने की क्षमता को सहज व सस्ता बनाती है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कानूनी ढांचे की यह विसंगति दर पहलू में रही है और इच्छाचल हाई कोर्ट की सर्किट या स्थानों खंडीत हो जाने पछले चालीस सालों से धर्मशाला के लिए हो रही है। ऐसे में कर्मचारी मामलों की मात्रावत् अर्जियों को शिमला में हाई कोर्ट का समय व प्रार्थनाकाल नहीं मिल पाता। यह दौरा है कि फैसलों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाते हुए बाजपा की अलग-अलग सरकारों ने कर्मचारियों को हाई कोर्ट का बार-बार विकल्प दिया, लेकिन इक्कीस हजार मामले अगर स्थानांतरित हो जाएं, तो अदालत के लिए इन्हें अपनी प्रार्थमिक भूमिका निभाना ठीक हो जाएगा। ऐसे में फिर एक नए प्रयाग के तहत सुकृष् सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दरवाजे खोलने की इच्छा प्रकट की है। अभी इससे संबंधित प्रक्रिया ने दस्तक दी है और इससे मुमुक्षुल होने की स्थिति तक है। कुछ समय का होंजा रहेगा। दोनों विकल्पों के बावजूद न हाई कोर्ट में मामले घटे और न ही प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के रास्ते कर्मचारी मामले कम हों।

कानून की शरण में कर्मचारियों के
प्रति सुविधानजनक मान्यताएँ
प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यवस्था के
बावजूद निष्पक्ष यही है कि कॉर्डर-
कॉर्डर, पद-पद और दफ्तर-दफ्तर
कार्य संस्कृति सुधारने के कई अधिक
दबाव यह है कि हजारों कर्मचारी
कानून छोड़-पैंगत तक ही सिमट रहे हैं।
पिछले काफी वर्षों से प्रदेश सरकारों ने
कर्मचारी समस्याओं को तरजूह देते हुए
उचित-अनुचित के बजाय उनके स्वायत्त
होने की सुधारें किया। न कभी
प्रशासनिक पोषण पर कोई महत्वपूर्ण
फैसला हुआ और न ही सरकारी
कार्यसंस्कृति में सुधार लाने के भीतर
प्रयास हुए। आश्चर्य यह कि हर साल
सैकड़ों ट्रांसफर मामलों की आपत्तियाँ
कानून की शरण पहुँच रही हैं, लेकिन न
कोई ठोस स्थानांतरण नियम या नीति
बनाने की ज़रूरत उठाई गई और न ही
कार्यसंस्कृति को अहमियत मिली। ऐसे
में क्या उस अपमानगर्क या मतदाता
की सरकार से अपेक्षाएँ पूरी हो रही हैं।

राय

अंतरिक्ष में नासा के दबदबे को खत्म करने का संकल्प पूरा करने के करीब पहुँच चुका है वाइना

हम आपको यह भी बता दें कि चीन के सरकारी मीडिया ने पिछले साल कहा था कि तियांगोंग पूरी तरह से चालू हो गया है। चीन ने यह भी कहा था कि ऐसे में जबकि आईएसएसए अपना जीवनकाल समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है तब चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कोई ढील नहीं देगा।

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अपने जीवनकाल के अंत वे करीब पहुँच चुका है। ऐसे में अल चीन की नजर अंतरिक्ष का बादशाह बनने पर लग गयी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को निर्देश दे रखे हैं कि हर हाल में आने वाले समय में चीन को अंतरिक्ष की दुनिया का सत्ताजमान बना दें। इसलिए चीन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास जोर कर दिये हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 74वें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में चीन को अंतरिक्ष एजेंसी चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (CAST) ने जग फुफु बताया है वह पूरी दुनिया को सावधान करने के लिए कह रही है। हम आपकी बता दें कि चीन की ओर से कहा गया है कि वह आने वाले वर्षों में अपने अंतरिक्ष स्टेशन को तीन से छह मॉड्यूल तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। जिससे अन्ध देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निकट जाने में अन्धों के लिए एक वैकल्पिक मंच उपलब्ध बन सकेगा। चीन ने कहा है कि चूँकि नासा के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) का कार्यक्रम समाप्त होने वाला है इसलिए दुनिया को अंतरिक्ष में अपने स्थानों के लिए एक विकल्प की जरूरत है जोकि वह उपलब्ध करायेगा। जरा सोचियें ! चीन जब भरती पर रह कर ही दुनिया की इतनी जासूसी करता है तो ऐसे में यदि अंतरिक्ष में उसकी बादशाहत हो गयी तो वह अपना पूरा अमला ही दुनिया की निगरानी करने में लगा देगा।

जहां तब अंतरिक्ष में चीनी स्टेशन को बता है ता उसको बारे में बताया गया है कि चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का परिचालन चीनी नवतारा 15 वर्ष से अधिक होगा। पहले इसका जीवनकाल मात्र 10 वर्षों का ही बताया गया था। हम आपको बता दें कि चीन का स्व-निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे जियांगोंग या चीनी में सेलेस्टियल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, वह 2022 के अंत से पूरी तरह चालू हो गया है। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन 450 किमी (280 मील) की कक्षीय ऊंचाई पर है और अभी यहां अधिकतम तीन अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। अभी चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है वह आर्टिफिशियल के मुकाबले 40 प्रगतिशत ही है क्योंकि नासा वेनेजुएल वाला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक साथ सात अंतरिक्ष यात्रियों को संभाल सकता है जबकि चीन का स्टेशन मात्र तीन अंतरिक्ष यात्रियों को ही एक साथ रह सकता है। इस्तीफा चीन ने अपने अपने अंतरिक्ष स्टेशन वे छह मॉड्यूल तक विस्तार को योजना बनाई है। हम आपको बता दें कि दो देशों को से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में मौजूद आर्टिफिशियल के 2030 के बाद निष्क्रिय होने की उम्मीद है। उससे पहले चीन का प्रयास है कि वह एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बन जाये। हम आपको यह भी बता दें कि चीन वे सकारणी मीडिया ने पिछले साल कहा था कि जियांगोंग पूर्ण तरह से चालू हो गया है। चीन ने यह भी कहा था कि ऐसे में जबकि आर्टिफिशियल अपना जीवनकाल समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है तब चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कोई डील नहीं देगा। चीन का यह भी दावा है कि कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चीनी स्टेशन पर भेजने के लिए आग्रह करना शुरू भी कर दिया है।

योगेंद्र योगी

केन्द्र की भाजपा सरकार ने पहले दिन से ही रुख साफ कर दिया कि किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई का भारत समर्थन नहीं करेगा। केन्द्र सरकार की यह नीति जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली आतंकी कार्रवाईयों से प्रभावित है।

इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध में हमारा केंद्र और आतंकी घटना की आलोचना करने की बजाए इजरायल की निंदा करने से साबित हो गया है कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अल्पसंख्यकों के वोट के लिए किस तरह तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं। यही वजह है कि बाजपा विपक्षी दलों पर आक्रामक रूख अख्तियार करती रही है। दरअसल विपक्षी दल आतंकी हमारा की निंदा करके देश के अल्पसंख्यक वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। इन सए युद्ध की शुरुआत आतंकी संगठन हमारा ने की। इसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोगों का आह्वान कर लिया। इसके विपरीत इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपना कर बाजपा को फिर से एक नया मुद्दा थमा दिया।

केन्द्र की भाजपा सरकार ने पहले दिन से ही रुख साफ कर दिया कि किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई का भारत समर्थन नहीं करेगा। केन्द्र सरकार की यह नीति जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली आतंकी कार्रवाइयों से प्रभावित है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में नये नये विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस को छोड़ कर ज्यादातर दलों ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। ऐसे मुद्दों पर विपक्षी दल ज्यादातर बचाव या विरोध की नीति ही अपनाते रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सहित नए भाजपा दलों का निशाना भी अल्पसंख्यक वोटों पर है। बौकल होता है। ऐसे में कोई भी दल सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया जाहिर करने से बचता है। इसमें हमारा से पहले हमला कर युद्ध को आमंत्रित किया, इसलिए विपक्षी दल स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे हैं। इसके विपरीत जम्मू-कश्मीर में धारा 370, तीन तलक और अयोध्या में राम मंदिर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करने में देर नहीं लगाई। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर की शांति और तर्कनीति का हालाल सर्वविदित है। पथरबाजी की घटनाएँ लालच भ्रम शून्य हो गई हैं। इस साल पर्यटकों की



रिकार्ड आमद दर्ज की गई है। जम्मू-कश्मीर से एक अग्निवीर का दस्ता तक सेना में शामिल हुआ है। जम्मू-कश्मीर में जी20 की बैठक हो चुकी है। इसी से स्पष्ट होता है कि गैरभाजपा दलों को किस तरह से अल्पसंख्यक वोट बैंक के तौर पर नजर आते हैं।

इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजरायल और हमस के बीच चल रहे कानूनी को लेकर फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें निराशा और पीड़ा व्यक्त की और फिलिस्तीनी लोगों के भूमि (जोने) और स्वशासन, ग्राम और समान के साथ (जीने) के अधिकार, प्रति अपने समर्थन को तबज्जो दी। हमस ने जिस तरह बच्चों और महिलाओं के कत्ल करके इंसानियत को शर्मसार किया, उस पर कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही अपहृत लोगों को रिहा किए जाने की अपील की। कांग्रेस महासचिव जगरम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी का हमेशा जगरम रहा है कि इजरायलियों की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सुनिश्चित करते हुए फिलिस्तीन के लोगों की वैध आकांक्षाओं को बाबू के दस मध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा ने ज़ोरदार हमला किया।

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक पोस्ट में कांग्रेस के बयान को अत्यंत निंदनीय बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रहित के खिलाफ

फैसला लेते हुए प्रस्ताव पारित किया है। एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस किस हद तक गिर सकती है ? उन्होंने कहा, अब कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने को तैयार है। हम और हमारी पार्टी भी विपक्ष में रही है लेकिन कभी भी राष्ट्रहित के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ नहीं उठाने प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा कि सीडीब्ल्यूसी मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध पर अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करती है, जब पिछले दो दिनों में एक हजार से अधिक लोग मारे गए हैं।

भाजपा ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस के शासन के दौरान हुई आतंकी वारदातों को गिना दिया। इसका एक वीडियो जारी करते हुए भाजपा ने कहा कि यूपीए के समय जुलै 2004 से मई 2014 तक भारत में 10, 262 आतंकी हमले हुए। जिसमें 7012 गिरफ्तारों की जात गई। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। जिसके बाद 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उज्जवाहल और हमास से जुड़े युद्ध के बीच कांग्रेस के प्रस्ताव की तुलना पाकिस्तान और तालिबान से की और आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के हित का बलिदान करना उसके डीएनए में है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रस्ताव में पाकिस्तान और तालिबान के बयानों से काफी समानताएँ हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस, पाकिस्तान और

तालिबान हमस की निंदा नहीं करते। इजराइल पर आतंकवादी हमले की निंदा नहीं करते और बंधक मल्लिओं और बच्चों के संबंध में चुप हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देशहित की बलि चढ़ाना कांग्रेस के डीएनए नहीं है। कांग्रेस बेशक फिलीस्तीन की दुहाई करेगा। आइं हमस की आतंकी कारवांयों की निंदा बेशक बचे रही हो किन्तु खाड़ी के कुछ देशों ने इसकी भरसना की है।

सूयुक्त अरब अमीरात ने हमला के हमले को गंभीर और नवाना बढ़ाने वाला बताया था। यूएन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा था कि वह इसराइली नागरिकों को उनके घरों से अगवा कर के बंदी बनाए जाने की खबरों से सन्तुष्ट है। बहरीन ने भी हमला के हमलों की आलोचना की है। बहरीन ने कहा था कि हमले ने तनाव को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। इन दोनों देशों के ये बयान उनसे पहले के स्तर से अलग है। जब पूरा अरब वर्ग इसराइल के खिलाफ एक सुर में बोला था। ईरान खुलकर हमला के समर्थन कर रहा है और इसराइल पर सीधे उगल रहा है। ईरान के विहों का अपना समीकरण है और उसी के हिसाब से वह प्रतिनिधित्व दे रहा है। कतर ने इसराइल को इस तनाव का अकेल जिम्मेदार बताया है। मलेशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी फिलस्तीनियों के समर्थन दिखाया है। खाड़ी देशों के इस तरह

अलग-अलग बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व में देशों के रिश्ते किस तरह बदल रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस सहित भारत के विपक्षी दल अभी तक ऐसे मसलों को सिर्फ वोट बैंक से नजरिए से देखते रहे हैं। भारत के संबंध खाड़ी देशों से लगातार बेहतर हो रहे हैं।

गौरतलब है कि हमारा क हमल से पहल सऊदी अरब और दूसरे देश इसराइल से संबं धित करने के लिए समझौता करने वाले थे। इस हमले के बाद हालात बदल गए हैं। इस हमले की वजह भी यही मानी जा रही है कि किसी तरह देशों में कोई समझौता नहीं होने पाए। कांफ्रेंस और विपक्षी दल इंडिया की तान बैठकों में अभी तब तक भी स्पष्ट नहीं हो सका कि परेलु और विदेशी मसलों पर नीति क्या रहेगी। इसी तरह भ्रष्टाचार और दूसरों मुद्दों पर भी विपक्षी गठबंधन की एकराय नहीं हो सकी। यह विपक्षी दलों की दुलमुल नीति का ही परिणाम है कि भाजपा के मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लेने में पीछे नहीं रही। देश और विदेश हितों से जुड़े भारत के मुद्दों पर राय कायम करने से पहल विपक्षी गठबंधन के कारण फलहाल सबसे बड़ी चुनौती चुनाव में सीट शेर्यारि की है। इस अथरक्षु एजेंडे के कारण ही विपक्षी एकता सिरे नहीं चल सकी है। विपक्षी गठबंधन में पारदर्शिता और स्पष्टता नहीं रही तो लोकसभा चुनाव में भाजपा की चुनौती का एकजुट होकर सामना करना आसान नहीं होगा।

क्रेडिट कार्ड अपग्रेड या लिमिट बढ़ाने से पहले इन बातों का रखें ख्याल, नहीं होगा कभी नुकसान

आज के समय में कैशलेस पेमेंट करना काफी लोग पसंद करते हैं। यह लेनदेन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आप यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिये आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लेनदेन के लिए करते हैं तो आपको बता दें कि एक समय के बाद आपको उसे अपग्रेड करवाने की जरूरत होती है। ऐसे में जब भी आप कार्ड को अपग्रेड करवाते हैं उस समय आपोक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

नई दिल्ली। आज के समय में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं। लगातार क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह जहां लेनदेन के प्रक्रिया को आसान करता है तो दूसरी तरफ यह सुरक्षित पेमेंट की सुविधा देता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पर मिल रहे लाभ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसे एक समय के बाद अपग्रेड करवा सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड या फिर स्विच करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिये बताएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

खर्चों का मूल्यांकन करें
दरअसल, जब भी हम क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करते हैं तो हमें कई सुविधा के साथ लिमिट बढ़ाने की भी सुविधा मिलती है। ऐसे में आपको कार्ड को स्विच



करने से पहले चेक करना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने एक्सपेंस का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके खर्च ज्यादा हो रहे हैं तो आप अपने कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं। परंतु आपको लिमिट बढ़ाने से पहले अपने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

एन्यूएल फीस और बाकी चार्ज पर ध्यान रखें
क्रेडिट कार्ड कंपनी ग्राहक से कई तरह के चार्ज लेती है। आपको चेक करना चाहिए कि कोई भी

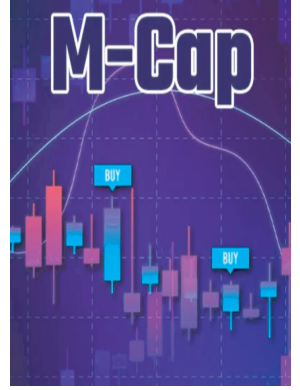
कंपनी आपसे कितने रुपये का सालाना चार्ज लेता है। ऐसे में आपको इस तरह के चार्ज की तुलना करने के बाद ही कार्ड को अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर आपको अपने वर्तमान कार्ड से ज्यादा एनुअल फीस का भुगतान करना पड़ता है तो ऐसे में आपको चेक करना चाहिए कि आपको कितना रिवाँर्ड मिल रहा है। आपको अपने खर्च के पैटर्न पर भी ध्यान देने होगा।

रिवाँर्ड बेनिफिट के बारे में जानें
क्रेडिट कार्ड कंपनी लेनदेन के साथ ग्राहक को रिवाँर्ड जैसे लाभ भी देती है। ऐसे में आपको यह

जरूर जान लेना चाहिए कि आपको कब कितना रिवाँर्ड मिल रहा है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड पर मिल रहे बेनिफिट की भी समीक्षा अवश्य करें। अगर आप किसी विशेष वस्तु पर ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्रेडिट कार्ड आपको उस वस्तु पर कितना और क्या लाभ दे रही है। इसके अलावा फेस्टिव सीजन में कई कार्ड पर ऑफर या प्रमोशन भी मिलता है। आपको इस पर भी नजर रखनी चाहिए। ऑफर या प्रमोशन लेते समय आपको नियम व शर्तों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहिए।

शेयर मार्केट की गिरावट ने टॉप-10 फर्म कंपनियों के M-Cap पर डाला असर, सबसे ज्यादा घटा इस कंपनी का बाजार एम-कैप

Stock Market Investors Wealth पिछले हफ्ते लगभग 6 करोड़ारी सत्र से शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट की वजह से देश की टॉप-10 फर्म के एमकैप में भी गिरावट हुई है। टॉप-10 फर्म के बाजार मूल्यांकन में 193181.15 करोड़ रुपये की संयुक्त गिरावट आई है। जाने देश के टॉप-10 फर्म की रैंकिंग



नई दिल्ली। देश के सभी टॉप-10 कंपनियों का पिछले सप्ताह बाजार मूल्यांकन में 1,93,181.15 करोड़ रुपये की संयुक्त गिरावट दर्ज हुई है। यह गिरावट की वजह शेयर बाजार में हो रही गिरावट को माना जा रहा है। इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और एचडीएफसी बैंक को हुई है।

पिछले हफ्ते की छुट्टियों में बीएसई बेंचमार्क 1,614.82 अंक या 2.46 प्रतिशत गिर गया।

टॉप-10 फर्म बाजार का मूल्यांकन

टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 52,580.57 करोड़ रुपये घटकर 12,25,983.46 करोड़ रुपये रह गया। यह अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 40,562.71 करोड़ रुपये घटकर 11,14,185.78 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मूल्यांकन 22,935.65 करोड़ रुपये घटकर 15,32,595.88 करोड़ रुपये और इंफोसिस का 19,320.04 करोड़ रुपये घटकर 5,73,022.78 करोड़ रुपये रह गया।

भारती एयरटेल का एमकैप 17,161.01 करोड़ रुपये घटकर 5,13,735.07 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस का एमकैप 15,759.95 करोड़ रुपये घटकर 4,54,814.95 करोड़ रुपये रह गया। आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 13,827.73 करोड़ रुपये घटकर 6,39,292.94 करोड़ रुपये और आईटीसी का मूल्यांकन 5,900.49 करोड़ रुपये घटकर 5,40,637.34 करोड़ रुपये रह गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमकैप 3,124.96 करोड़ रुपये घटकर 5,83,098.06 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक का एमकैप 2,008.04 करोड़ रुपये घटकर 5,00,670.73 करोड़ रुपये रह गया।

टॉप-10 फर्म की रैंकिंग
देश में टॉप-10 फर्म की लिस्ट में सबसे टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, आईटीसी, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक और बजाज फाइनेंस हैं।

इनसाइड

एयरटेल ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ की पार्टनरशिप, अब ग्राहकों को मिलेगी इंटीग्रेटेड कॉलिंग की सुविधा



टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इंटीग्रेटेड कॉलिंग को लेकर साझेदारी हुई है। अब ग्राहकों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से फोन कॉल की सुविधा मिलेगी। अभी तक यह सुविधा केवल एंटरप्राइज ग्राहकों को मिलती है। इस साझेदारी से ग्राहकों के लिए स्केलेबिलिटी सुनिश्चित होगी। आइए रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से फोन कॉल की सुविधा मिलेगी। इस तरह के कॉल को इंटीग्रेटेड कॉलिंग कहा जाता है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि यह पहली बार है कि देश में कोई ओवर-द-टॉप प्लेयर मोबाइल और लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट किया जाएगा। अभी यह सुविधा केवल एंटरप्राइज ग्राहकों को मिलती है।

एयरटेल आईक्यू, बिजनेस हेड, अभिषेक बिस्वाल ने बयान में कहा माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक के साथ कनेक्टिविटी की एयरटेल की पारंपरिक ताकत के परिणामस्वरूप विश्वसनीयता, लागत बचत, प्रबंधन में आसानी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्राहकों के लिए स्केलेबिलिटी सुनिश्चित होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आम जाकर वे केवल उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह नई सर्विस उद्यमों को काम के प्रवाह के भीतर संचार और सहयोग को सुव्यवस्थित करने वाली टीमों के अनुभव के माध्यम से बाहरी उपयोगकर्ताओं को कॉल करने और लेने में सक्षम बनाएगी। माइक्रोसॉफ्ट, कट्टी हेड, मॉडर्न वर्क एंड सरफेस, भारत और दक्षिण एशिया, श्रुति भाटिया ने कहा हम एयरटेल के साथ साझेदारी करके और एक अभिनव समाधान पेश करके रोमांचित हैं जो भारत के कार्यकाल को उत्पादकता, सहयोग और दक्षता के एक नए स्तर को अनलॉक करने में सक्षम बनाएगा, जिससे देश में काम का भविष्य बदल जाएगा।



इस हफ्ते निवेशकों को कमाई के लिए मिलेंगे बंपर मौके सेले वर्ल्ड के अलावा कई एसएमई कंपनी खोलेगी अपना आईपीओ

IPO Next Week शेयर बाजार में आईपीओ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस तिमाही 20 से ज्यादा कंपनी अपने तिमाही नतीजों का एलान करेगी। इस हफ्ते शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। यह सभी कंपनी आईपीओ से जुटाए राशि का इस्तेमाल कंपनी के विकास के लिए करेंगे।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्ट होन के लिए कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। जब भी कंपनी अपना विकास करने के लिए फंड जुटाने की कोशिश करती है तो वह शेयर बाजार में लिस्ट होना काफी पसंद करती है। कल से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में कई एसएमई कंपनी अपना आईपीओ खोलने वाली है। इन आईपीओ का जलवा शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। जानिए, इस हफ्ते कौन-सी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं।

सेलो वर्ल्ड आईपीओ
सेलो वर्ल्ड (Cello World) अपना आईपीओ 30 अक्टूबर 2023 यानी कि कल निवेशकों के लिए खोल रहा है। यह आईपीओ 1 नवंबर 2023 को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ में 1,900.00 करोड़ रुपये का बुक बिल्ट इश्यू कर रही है। यह पूरा इश्यू



ऑफर फॉर सेल है। इसके लिए कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 617 रुपये से 648 रुपये तय किया है। 127 अक्टूबर को कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खोला गया था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 567 करोड़ रुपये जुटाए हैं। नवंबर में कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की संभावना है।

होनासा कंज्यूमर लिमिटेड आईपीओ
मामाअर्थ की कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड (Honasa

Consumer Limited) भी निवेशकों के लिए अपना आईपीओ खोल रहा है। कंपनी का आईपीओ 31 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर 2023 को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ में 365.00 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू जारी करेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 308 रुपये से 324 रुपये है।

ट्रान्स्टील सीटिंग टेक्नोलॉजीज आईपीओ
इस हफ्ते एसएमई आईपीओ भी खुल रहे हैं। कल यानी 30 अक्टूबर 2023

को ट्रान्स्टील सीटिंग टेक्नोलॉजीज (Transtee Seating Technologies) का आईपीओ निवेशकों के लिए खुलेगा। अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आप 1 नवंबर 2023 तक ही इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का मूल्य 67 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर है। इसके अलावा एसएमई में बाबा फूड प्रोसेसिंग, एसएआर टेलीवेंचर, मिश डिजाइन, वृंदावन प्लांटेशन का आईपीओ भी लॉन्च होने वाला है।

एसबीआई ने एमएस धोनी को बनाया अपना ब्रोड एम्बेस्डर, अब बैंक के हर कैंपेन में दिखेगा माही का चेहरा

SBI Brand Ambassador MS Dhoni देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने नए ब्रांड एम्बेस्डर की घोषणा कर दी है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी विज्ञापनों में महेंद्र सिंह धोनी का चेहरा देखने को मिलेगा। बैंक ने धोनी के साथ हुई साझेदारी को एक आदर्श बताया है।

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने रविवार को क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की। इस को लेकर बैंक द्वारा बयान दिया गया कि अब बैंक के सभी प्रचारों में धोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

बैंक ने अपने बयान में कहा कि धोनी में तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखने के साथ दबाव में स्पष्ट सोच और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता है। इस क्षमता के बारे में पूरा देश जानता है। महेंद्र सिंह धोनी का ब्रांड एम्बेस्डर बन जाना यह एएसबीआई के लिए एक आदर्श



विकल्प है। बैंक ने यह कहा कि अब बैंक और धोनी का संबंध जुड़ाव विश्वसनीयता और नेतृत्व के मूल्यों को दर्शाते हैं। इसी के साथ एसबीआई ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाने की बैंक को

प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा एक संतुष्ट ग्राहक के रूप में धोनी का एसबीआई के साथ जुड़ाव उन्हें हमारे ब्रांड के



लोकाचार का एक आदर्श अवतार बनाता है। इस साझेदारी के साथ हमारा लक्ष्य विश्वास, अखंडता और अटूट समर्पण के साथ राष्ट्र और अपने ग्राहकों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

पीएम किसान योजना की लाभार्थी लिस्ट हुई जारी, इन स्टेप को फॉलो करके चेक करें अपना नाम

PM-KISAN 15th Installment Date 2023 देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जल्द ही किसानों के अकाउंट में पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जमा करने वाली है। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन दिया है तो आप आसानी से अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक कर सकते हैं।



नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 2018 के अंत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस स्कीम में हर साल किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये की राशि जमा होती है। यह राशि किस्तों में मिलती है। इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्कीम की 14वीं किस्त जारी की गई थी। अब देश के करोड़ों किसान 15वीं किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने भी इस योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो आप अब आसानी से अपना नाम पीएम किसान योजना के लाभार्थी लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

लाभार्थी लिस्ट में चेक करें अपना नाम
आपको सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की अधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाना है।

इसके बाद आपको पोर्टल पर शो हो रहे Know Your Status के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।

इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप Know your

registration no. के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना है। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। अगर आप अपने साथ अपना गांव के लोगों का नाम भी देखना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर Beneficiary List के विकल्प को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करना है।

इसके बाद आप Beneficiary List को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके नाम के साथ गांव में और किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर
पीएम किसान योजना से जुड़े किसी भी समस्या के लिए आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान स्कीम का स्टेटस चेक करने के लिए आप 155261 पर कॉल कर सकते हैं।

नवंबर में है दिवाली, छठ पर्व की वजह से बंद रहेंगे 15 दिन बैंक, जानिए हॉलिडे लिस्ट

नई दिल्ली। केंद्रीय बैंक ने नवंबर 2023 के बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है। इस साल नवंबर महीने में कई त्योहार और वीकेड है। इस वजह से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। वैसे ग्राहक बैंक हॉलिडे के दिन ऑनलाइन नेट बैंकिंग और एटीएम के जरिये ट्रान्जेक्शन कर सकते हैं। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार देश के सभी बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को सभी बैंक बंद रहेंगे। अगर आप भी बैंक जाकर कोई काम करवाने का सोच रहे हैं तो आपको बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करना चाहिए। जानिए, आपके शहर में कब-कब बैंक बंद रहेंगे।

बैंक हॉलिडे लिस्ट	तारीख	अवकाश का कारण	जगह
1 नवंबर 2023	करवा चौथ	बैंगलोर, इफाल, शिमला	
10 नवंबर 2023	वंगाला महोत्सव	शिलांग	
11 नवंबर 2023	दूसरा शनिवार	पूरा देश	
12 नवंबर 2023	रविवार	पूरा देश	
13 नवंबर 2023	गोवर्धन पूजा	अगरतला, देहरादून, गैंगटोक, इफाल, जयपुर, कानपुर, लखनऊ	
14 नवंबर 2023	दीपावली	गैंगटोक, इफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, शिमला	
15 नवंबर 2023	भाई दूज	छठ पर्व	पटना, रांची
20 नवंबर 2023	छठ पर्व	पटना, रांची	
23 नवंबर 2023	इमास-बगवाल	शिलांग, देहरादून	
25 नवंबर 2023	चौथा शनिवार	पूरा देश	
26 नवंबर 2023	रविवार	पूरा देश	
27 नवंबर 2023	गुरु नानक जयंती		



बढ़ते वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने उठाया कदम एक नवंबर से इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री

राजधानी दिल्ली में एक नवंबर से केवल सीएनजी इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसों को एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनसीआर से आनेवाली बसें दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है। इन इलाकों से एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आती। यहां से बीएस 3 और बीएस 4 बसें ही दिल्ली में आती है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि एक नवंबर से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं भारत स्टेज (बीएस) - 6 बसें ही एंट्री ले सकेंगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में संचालित होने वाली बीएस-3 और बीएस-4 बसों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित करे। एक नवंबर से सभी एंट्री प्वाइंट पर परिवहन विभाग द्वारा एक चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।

गोपाल राय वाहन प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में कश्मीरी गेट आइएसबीटी का निरीक्षण किया। उन्होंने एनसीआर से आने वाली डील बसों के चालकों को इस बारे में जानकारी भी दी।

दिल्ली में 800 इलेक्ट्रिक बसें चल रही

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अभी के समय में गाड़ियों से प्रदूषण कहीं ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में सभी बसें सीएनजी पर चल



रही हैं। 800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के एनसीआर जिलों से चलने वाली बीएस-3 और बीएस-4 डील बसों के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है।

यूपी-हरियाणा से आ रही बीएस 3

और 4 बसें
आइएसबीटी में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया गया कि यूपी और हरियाणा से जो भी बसें यहां आई हैं, वो सब बीएस-3 और बीएस- 4 हैं। वहां से कोई भी बसें अभी इलेक्ट्रिक और सीएनजी की नहीं आई हैं।

इसीलिए हम मांग करते हैं कि केंद्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में संचालित होने वाली बीएस 3 और बीएस 4 बसों पर प्रतिबंध लागू करें।

एनसीआर के प्रदूषण का प्रभाव दिल्ली पर

राय ने आगे कहा कि एनसीआर के प्रदूषण का प्रभाव भी दिल्ली पर पड़ता है। अतः एनसीआर में इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं बीएस-6 बसों को ही अनुमति दी जाए। वहां बीएस-3 एवं बीएस-4 बसों पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू की जाए।

वेस्ट हलके के विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू की अगुवाई में वार्ड नंबर 72 और 74 में हरिंदर सिंह संधू और शमशेर सिंह संधू की देखरेख



अमृतसर (साहिल बेरी) इलाके की कच्ची गलियां, जिन पर लंबे समय से किसी पार्टी का ध्यान नहीं गया है। समय, लेकिन आम हैं जैसे ही आदमी पार्टी पंजाब में आई, लोगों की समस्याएं हल होनी शुरू हो गईं। सरदार शमशेर सिंह संधू जी और सरदार हरिंदर सिंह संधू जी, आम आदमी पार्टी के मेहनती और सक्रिय सेवक, जिन्होंने इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें, आज बहुत मेहनत की। हम लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी के सेवादार शमशेर सिंह संधू और हरिंदर सिंह संधू का समर्थन करें।

केरल में धमाके के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली, सभी चर्च और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई; चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

केरल के एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान हुए धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी के सभी चर्च और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल केंद्रीय जांच एजेंसियों के संपर्क में है।

नई दिल्ली। केरल के कलामासेरी स्थित कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके के बाद दिल्ली में भी चेतावनी जारी की गई है। यहां पर दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी के सभी चर्च और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले, दिल्ली के सभी चर्च की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल केंद्रीय जांच एजेंसियों के भी संपर्क में है, ताकि इस संबंध में कोई इनपुट इन्हें मिल सके।

एनएच बहाली में बाधा बना भूस्खलन किन्नौर जिले में फंसा लाखों पेट्टी सेब

एनएच प्राधिकरण रामपुर के एक्सईएन केएल सुमन ने बताया कि नाथपा में बाधित हुए नेशनल हाईवे पांच का करीब 50 मीटर हिस्सा खोल दिया गया है। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके चलते एनएच बहाली का कार्य प्रभावित हो रहा है।



भवानगर (किन्नौर)। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे- 5 नाथपा में दूसरे दिन भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया। पहाड़ी से भूस्खलन और चट्टानें दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस कारण हजारों लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। किन्नौर जिले में सेब की लाखों पेट्टियां फंसी हुई हैं। हालांकि, एनएच प्राधिकरण ने हिमाला की ओर से 30 और किन्नौर की ओर से करीब 20 मीटर सड़क को बहाल कर दिया है, लेकिन डेढ़ सौ मीटर सड़क अब भी मलबे से ढकी हुई है।

गौरतलब है कि शनिवार रात करीब दो बजे से नाथपा में पहाड़ी से चट्टानें और भूस्खलन का सिलसिला जारी है। पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण एनएच का करीब 200 मीटर हिस्सा चट्टानों और मलबे के ढेर से दब गया है। इस कारण जिले किन्नौर के हजारों लोगों सहित देश-विदेश से किन्नौर आने

वाले पर्यटकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। रविवार को दूसरे दिन नेशनल हाईवे प्राधिकरण की मशीनें और मजदूर बाधित सड़क को बहाल करने में जुटे रहे, लेकिन पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन से मजदूरों की जान को भी जोखिम बना हुआ है। रविवार को परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को ट्रांसमिट कर भेजा गया, जबकि छोटे वाहनों ने प्लॉगी वाया निचार होकर किन्नौर का रुख किया। पहाड़ी से भूस्खलन का सिलसिला न थमने के कारण अभी एनएच की बहाली में तीन से चार दिन का समय लग सकता है। प्राधिकरण ने एनएच की बहाली के लिए मौके पर पांच मशीनें और करीब 20 मजदूरों को तैनात किया है, जो युद्धस्तर पर मार्ग बहाली में जुटे हुए हैं। उधर, एनएच प्राधिकरण रामपुर के एक्सईएन केएल सुमन ने बताया कि नाथपा में बाधित हुए

नेशनल हाईवे पांच का करीब 50 मीटर हिस्सा खोल दिया गया है। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके चलते एनएच बहाली का कार्य प्रभावित हो रहा है।

फिकअप में निकाली जाएगी सेब की फसल
नाथपा में एनएच बाधित होने के कारण जिले में चल रहा सेब सीजन भी प्रभावित हो गया है। जिले में अभी भी सेब की लाखों

पेट्टियां मंडी भेजी जानी हैं, लेकिन नाथपा में सड़क बाधित होने के कारण बागवानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि मंडी के लिए वाया कुंजुम दर्रा होकर सेब की फसल भेजी जा सकती है, लेकिन यह दर्रा भी बाधित होने के कारण यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया है।

ऐसे में अब जिला प्रशासन की ओर से वांगतू, निचार वाया प्लॉगी होकर सेब की फसल फिकअप के माध्यम से मंडी भेजे जाने की पहल की जा रही है। उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग प्लॉगी निचार होते हुए सेब की फसल को मंडी भेजने की योजना बनाई जा रही है। जल्द ही समय निर्धारित कर फिकअप और छोटे मालवाहक वाहनों की मदद से इस मार्ग होते हुए सेब मंडी भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

हॉर्न बजाने पर एपीएसआरटीसी के बस चालक पर हमला, सात लोग गिरफ्तार

नेल्लोर जिले में कावली के पास एपीएसआरटीसी बस के चालक पर हमला करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान की।

नेल्लोर जिले में कावली के पास आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) बस के चालक पर हमला करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

रोडरेंज की घटना में सात से ज्यादा लोगों ने बस चालक बी रामसिंह (52 वर्षीय) पर हमला कर दिया था। नेल्लोर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के तिरुमलेश्वर रेड्डी ने बताया कि 26 अक्टूबर को जब बस कावली मछली बाजार के पास पहुंची तो राम सिंह ने सामने वाली कार के लिए हॉर्न बजाया। इससे लोग नाराज हो गए और उन्होंने राम सिंह पर हमला कर दिया।

हालांकि, इस मुद्दे को वहां सुलझा लिया गया था, लेकिन सात लोगों ने दो कारों से बस का पीछा किया और मधुपाडु सर्विस रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-16 के पास राम सिंह को रोका और उन पर हमला कर दिया।

आरोपियों ने राम सिंह को चालक की सीट से खींचकर पीटा। इस दौरान उन्होंने सहायक चालक टी. श्रीनिवासन राव को भी नहीं बख्शा। इस घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीमों का गठन



किया और हमले के उस वीडियो से आरोपियों की पहचान की, जो वायरल हो गया था। इसके पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अन्य फरार लोगों की तलाश की जा रही है।

अंबाला रिंग रोड के 22 किलोमीटर के हिस्से का काम शुरू

अंबालासिटी। अंबाला के ट्रैफिक को छोड़कर सीधे पंजाब और अन्य राज्यों में आवाजाही करने के लिए यात्रियों को अधिक इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने वादे के अनुसार अंबाला रिंग रोड पर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। अंबाला रिंग रोड का 18 किलोमीटर के हिस्से पर पहले ही काम चल रहा है। वहीं, अब 22 किलोमीटर के हिस्से पर भी निर्माण शुरू हो गया है। इसमें रिंग रोड को बनाने के लिए जो जमीन अधिगृहीत की गई है उससे मिट्टी हटाई जा रहा है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से अंबाला रिंग रोड के कार्य के शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, क्योंकि फंड के अभाव में काम अटका हुआ था। सभी को लग रहा था कि कहीं कार्य में देरी न हो जाए। मगर इसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में काम शुरू कराने की बात कही थी।

परिवहन मंत्री गडकरी से हो चुकी बात : ऐसे अब निर्माता कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया है तो इस परियोजना को समय पर पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के लिए गृहमंत्री अनिल विज ने खुद भी प्रयास किया है। वे इसके लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी इस बाबत मिल चुके हैं।

दो फेज में 1100 करोड़ की परियोजना : दरअसल, अंबाला 40 किलोमीटर के सिकस लेन रिंग रोड की पूरी लागत 1100 करोड़ रुपये की है। इसमें से भूमि अधिग्रहण पर करीब 686 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इस रिंग रोड को दो फेज में बनाया जाना है। इसमें पहला फेज 18 किलोमीटर है। इस पर काम कुछ समय से चल रहा है। वहीं, 22 किलोमीटर के दूसरे फेज पर काम शुरू 11 अक्टूबर को शुरू कर दिया गया था। इस रिंग रोड को केंद्र और हरियाणा दोनों 50-50 फीसद का खर्चा उठाकर इसका निर्माण करा रहे हैं।

एमसीडी लाइब्रेरी में रखी आपत्तिजनक बुक को फूँका

परिवहन विशेष। एसडी सेवी।

बरवाला पंचायत 360 के संस्थापक, एनपीसीएस प्रमुख एवं संयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षक मंच के सुप्रीमो राम किशन पूनिया के नेतृत्व में पंचायत के कई सदस्यों ने रविवार को भारी पुलिस बंदोबस्त, सीआईडी कर्मियों के बीच दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी गई किताब में मौजूद कथा /कहानी को बेहद ही आपत्तिजनक बताते हुए सैक्टर 11 रोहिणी स्थित आम्बेडकर भवन के बाहर फूंक कर

अपना विरोध प्रकट किया। पंचायत के महासचिव कपिल देव कटारिया, प्रचार सचिव धन सिंह धुनिया ने बताया कि 'भारत की लोक कथाएं' नामक किताब एमसीडी के स्कूलों में लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है। जिसमें एक कथा बहुत ही आपत्तिजनक है। इसमें अनुसूचित जाति की उपजाति के संदर्भ में घोर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। जिसकी जनसंख्या देश में करोड़ों में है। उन्हें इस कथा की भाषाशैली से गहरा आघात पहुंचा है।

पंचायत के प्रधान दयाचंद थानेदार ने कहा कि अगर इस पुस्तक पर चर्च प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो दिपावली के दिन दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक और कमिश्नर के घर के सामने इस पुस्तक को फूँका जाएगा। बरवाला पंचायत 360 के संस्थापक एंड संयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षक मंच के सुप्रीमो राम किशन पूनिया ने बताया कि आज रविवार को पंचायत के 6 सर्वोच्च पदाधिकारियों जिनमें कपिल देव कटारिया, उपाध्यक्ष वरिष्ठ राजेंद्र सिंह जंगला,

सचिव धन सिंह धानिया, अध्यक्ष दयाचंद थानेदार, और बवाना बानानी के

प्रधान थानेदार पूर्ण चंद रंगा ने आज रविवार को तो सिर्फ सांकेतिक रूप से इस पुस्तक के आपत्तिजनक अंश को जलाया है। दिवाली के बाद शिक्षा निदेशक और कमिश्नर एमसीडी को बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर 26 नवंबर को संसद के सामने जंतर-मंतर पर भारी भीड़ के सामने विरोध स्वरूप इस पुस्तक को फूँका जाएगा।

जन आधार मंच

(सोसाइटी एक्ट 1960 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था)

के द्वारा संचालित मुख्य गतिविधियां

नागरिकों में जागृति
(आम जन में रचनात्मक सृजन)

रोटी बैंक रोहिणी
(जरूरतमंदों के लिए नि:शुल्क भोजन व्यवस्था)

पूजा अवशेष बैंक
(पर्यावरण व जल संरक्षण अभियान)

Useless is Not always Waste
(किसी की अनुपयोगी वस्तुओं को जरूरतमंदों को उपलब्ध कराना)

पारदर्शी सफ़र
(सामाजिक मुद्दों व क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करने का प्रयास)

आर्थिक सहयोग

A/C Name : JAN AADHAR MANCH

Bank Name : UCO BANK

IFS CODE : UCBA0001872

A/C NO. : 18720110040454

Bank Add. : PRASHANT VIHAR, DELHI-85

Paytm No. 9311016424

आपका सहयोग 80G के अंतर्गत आयकर से मुक्त है

हेल्पलाइन : 9311016424

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेसंस प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18, 19, 20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, ग्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095, newstransportvishesh@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होगा। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023